

आमृत विचार

मुरादाबाद

अहम बातें

- एमएसएमई : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान
- एफएंडओ पर एसटीटी 0.02 से 0.05 फीसदी की गई
- 17 कैसर की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

- नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप
- नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा
- किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टैक सपोर्ट देगी सरकार

इस बार इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं

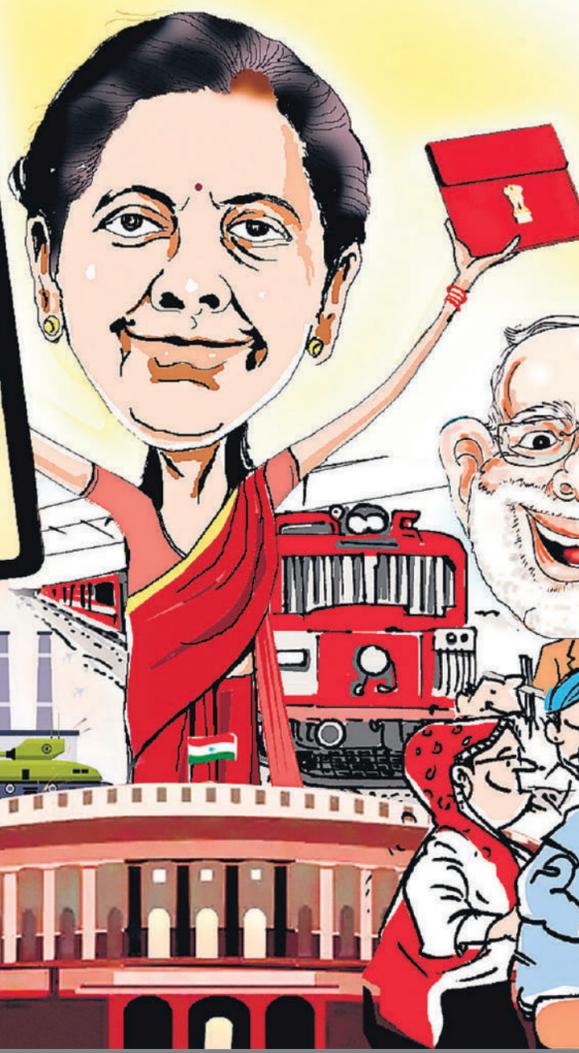
बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस

7,84,678 रक्षा	2,77,830 रेलवे	1,39,289 शिक्षा	1,06,530 स्वास्थ्य	2,55,233 गृह मंत्रालय सभी राशि करोड़ रुपये में
-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	--

टैक्स वही, सोच नई

53.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश

85 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिखलाई भविष्य की झलक



बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टैक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य

यह हुआ महंगा

- इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना : टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
- चल संपत्ति का खुलासा न करना : अब इस पर पेनल्टी लगेगी
- स्टॉक ऑफ़िश और फ्यूचर्स ट्रेडिंग : सिक्वोरिटीज ट्रांजिजेशन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
- छत्ते और उनके पाटर्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) इयूटी लगेगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रेप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर इयूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर इयूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

सस्ती हुई चीजें

- माइक्रोवेव ओवन के खास पाटर्स पर अब बेसिक करस्टम इयूटी नहीं
- चमड़े के नियात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इन्पुट्स को इयूटी-फ्री आयात की सुविधा
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर करस्टम इयूटी माफ
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर करस्टम इयूटी हटी
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक करस्टम इयूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पाटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर करस्टम इयूटी माफ
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5-20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर की गई
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगेगा।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक करस्टम इयूटी माफ
- प्रोजेन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफ़ल पर टैरिफ 30 से घटाकर 5 प्रतिशत
- ऑटोमिा सिस्ट और कैसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बेजोख नियमों में ढील के साथ स्वयं-व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा



मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और

वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

- सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।
- आर्थिक ग्रोथ** : सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- जनता की उम्मीद** : दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- सबका साथ, सबका विकास** : सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है।

एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार धराशायी, सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा



मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को धरलु शेर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी विक्रवाली के दबाव में निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ रुपये ड्रॉ गए। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का एलान बाजार को परस नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयर्स पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर खिसक गया था।

सात साल में सबसे बड़ी गिरावट, वित्त मंत्री बोलीं- सड़हबाजी को रोकना है मकसद, निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748.9 अंक यानी 2.95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। एचडीएफसी सिक्वोरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पवधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घवधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणादायी संकल्प-पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। योगी ने कहा यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को संरक्षित बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 प्रतिशत से कम है। कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तान्तरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

टैक्स, उद्योग और कृषि



आयकर में नहीं मिली राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट में आमजन की टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को आशा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। इसके मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना था। यही सीमा अब 2026-27 में भी लागू रहेगी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पूर्व की भांति 75 हजार ही रहेगा। ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रह गए।



टैक्स में कुछ इन छूट का भी ऐलान

वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब किसी मोटर एक्सिजेंट वलेम के तहत तय ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेबर सर्विस को टीडीएस के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है और इन सेवाओं पर 1 से 2 फीसदी की टीडीएस कटौती हो सकती है।



छोटे करदाताओं को राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। अब आईटीआर फाइल करने पर कम या जीरो टैक्स कटौती सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपॉजिट्री, निवेशक के फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे उन कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेश में घूमना, इलाज और पढ़ाई अब पहले से सस्ती

सरकार ने विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस जो पहले 5-20 फीसदी लगता था, को घटाकर सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा। इससे विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा।



आईटीआर के लिए नई डेडलाइन

अब आईटीआर-1 और 2 को भरने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। नॉन-ऑडिटेड बिजनेस को आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है। वहीं एनआरआई के लिए टैन की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने पर निवासी खरीदार के पैर पर चालान के जरिए टीडीएस जमा किया जा सकता है।

एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह छह दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। आयकर अधिनियम-2025 के नियम तथा 'टैक्स रिटर्न' फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

63,500- करोड़ रुपये बजट में किसान सम्मान निधि के लिए जारी किए गए हैं। पिछली बार भी इस योजना के लिए इतनी ही धनराशि का आवंटन किया गया था। इस तरह 6000 रुपये सालाना की किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी।

वित्त मंत्री ने बजट में किया स्मार्ट फार्मिंग एआई टूल 'भारत विस्तार' का एलान

खेती में एआई क्रांति से किसान होंगे मालामाल

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रस्ताव और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एआई टूल 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) को माना जा रहा है। यह एक बहुभाषीय एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संसाधनों को एआई प्रणाली से जोड़ेगा। इसका मकसद किसानों को उनकी अपनी भाषा में खास सलाह देना, खेती के जोखिमों को कम करना और पैदावार बढ़ाकर बेहतर फैसला लेने में मदद करना है। इससे किसान आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। यह खेती से प्राप्त डेटा और सरकारी एपीआई से मिली जानकारी का उपयोग करता है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। 'भारत विस्तार' का ऐलान सबका साथ विकास कर्तव्य का हिस्सा है। इसके अंतर्गत फसल चयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बीज-खाद और कीटनाशक की सलाह के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा ट्रेकिंग जैसी सारी जानकारी एक ही इंटरफेस पर किसान को उसकी अपनी भाषा में मिलेगी। इस तरह यह प्लेटफॉर्म फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के बेहतर निर्णय में मदद करेगा तथा कस्टमाइज्ड एडवाइजरी से जोखिम कम करेगा।



यूनिकाइड सिस्टम और एआई चैटबॉट

भारत विस्तार एआई टूल किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित सिस्टम है, जो मौसम, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करेगा। इसके तहत किसानों को एआई चैट बॉट, यूनिकाइड सिस्टम और टैरिंटिंग की जानकारी दी जाएगी। कृषि साथी एआई चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे। इसमें वे वीडियो के जरिए भी समाधान हासिल कर सकेंगे।



कोकोनट प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ किसानों को लाभ

भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल संवर्धन योजना के माध्यम से नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुराने और कम पैदावार देने वाले पेड़ों को नए पीढ़ों और किस्मों से बदलने का काम किया जाएगा।



20 हजार से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी

पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सख्ति योजना पेश की है। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।



पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलने से बढ़ेगी किसान की आमदनी

→ **1,62,671** रुपये कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन

→ **7%** अधिक है यह राशि पिछले साल के बजट आवंटन से

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंग्ड सॉल्विडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्टी और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करके डेयरी और मुर्गीपालन के लिए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सुजन को संवर्धित करके और पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। बजट में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना तैयार करने की बात भी कही गयी। इससे रेशम किसानों, भेड़ पालक किसानों और जूट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

मृत्यु पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मृत्यु पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा।



उद्योग जगत

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को 40 हजार करोड़ तो कंटेनर के वैश्विक इकोसिस्टम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये

मैनुफैक्चरिंग और एमएसएमई बनेंगे विकसित भारत की राह में गेम चेंजर

नई दिल्ली, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत में मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग को गति देने का प्रस्ताव किया है। इसमें बायोफार्मा में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण को योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत उपकरणों और आईपी डिजाइन पर विशेष जोर दिया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर (रेयर अर्थ कॉरिडोर) और 3 समर्पित

एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए 10,000 करोड़ का कोष

200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे आधुनिक

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इविटो समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इविटो समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एमएसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेडिंस मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी को लेनदेन ट्रेडिंस मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जौईएम को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सरता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। एमईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार में बिक्री के लिए रियायती शुल्क की सुविधा। कंटेनर विनिर्माण का अगले 5 वर्षों में वैश्विक इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए नेशनल फाइबर मिशन और में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

'कॉरपोरेट मित्रों' का दस्ता एमएसएमई की करगा मदद: सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता

का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार इस दस्तों को तैयार करने के लिए आईसीएसआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई जैसे संस्थानों को मांड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग देगा।

"भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैनुफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।



उद्योग जगत ने बताया दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बजट

नयी दिल्ली। केंद्रीय बजट को भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रसायन, पुर्जिगत वस्तुएं, वस्त्र, खेल सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट कर अवकाश

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक 'कर अवकाश' का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को वलाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ' मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तरीय ग्राहकों को वलाउड सेवाएं प्रदान करती है। ' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रय इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी वलाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

स्वस्थ भारत

स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10% पिछली बार से ज्यादा

निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।



अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्यूटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए टोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।



दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑटोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एलाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑटोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एलाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 नए क्षेत्र शामिल होंगे।

कैंसर के साथ सात अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें होंगी कम



नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के साथ सात और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रियायतों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी यानी इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सात और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं के आयात शुल्क में भारी छूट दी गई है। मूलभूत सीमा शुल्क वह टैक्स है जो भारत सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाती है और यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लिया जाता है। इस फैसेले का सबसे बड़ा असर कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के काम में आने वाली दवाओं की कीमत पर पड़ेगा।

● बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान



नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अखंड गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बढ़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा कि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।



पहला निमहांस बैंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तंत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई

विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी



एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने

शिक्षित भारत

8.27% से ज्यादा वृद्धि



21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति दर्शाता है सरकार की प्राथमिकता को : प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नवर्गिंग इनोवेशन, इंटरप्रैन्वोरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है



इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।



शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।



में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध, नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम

- 2025-26 में 2.52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

है कि वह परिस्पर्धित बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई परिवहन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25

सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और परिचम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सुरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यवरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारों मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यवरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सुरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025-26 की बात है, कमाई और खर्च

के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हम इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्विचार और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियाँ आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।



बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020-21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई। इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें



मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत

व्यय 1,86,454 करोड़ रुपये अनुमानित था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1.39 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा) वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा आवंटन अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत है और यह 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 15.19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

- 1.85 लाख करोड़ में सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रावधान
- 1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए व्यय करने का प्रावधान
- 17,250 करोड़ अनुसंधान व विकास पर होगा खर्च
- 12,100 करोड़ भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए

खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए हैं जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये थे। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सफलता को और सुदृढ़ किया है।

डीआरडीओ के लिए बजट कमी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक

कोलकाता। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनॉय दास ने कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कमी भी बाधा नहीं रहा है। दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बिना शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है। दास के मुताबिक, डीआरडीओ से अमली पीढी की ऐसी तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्होंने साइंस सिटी सभागार में कहा कि हमें ऐसे उपकरणों पर काम करना होगा, जिनका हमारे सशस्त्र बल सपना देख रहे हैं। हम ऐसे उपकरणों के आयात का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और युद्ध के परिदृश्यों में समीकरण बदल गए हैं। दास को विज्ञान और रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में योगदान के लिए जेआईएस महा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह बजट हमें उन प्रणालियों को साकार करने और सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिन्हें हम विकसित करते हैं। यह निर्यात के माध्यम से आर्थिक महाशक्ति बनने में सहायक होगा। पहले भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात से वंचित रखा गया था और आज हम आयात से इन्कार कर रहे हैं। भारत ने गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करके समीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है और पूनः आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है।

5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु, सुरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बनाने का उद्देश्य बताया कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरो पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं - शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों गंगवुड, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-इरोड-तिरुपुुर, पुणे, सुरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विधि मंत्रालय को ईपीआई के लिए मिले 250 करोड़

मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच बजट में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 500 करोड़ अलग से दिए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 99 करोड़ है। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-अदालत परियोजना को मिला 1,200 करोड़

सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना के तृतीय चरण के लिए केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमान के 1,500 करोड़ के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सुचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई-अदालत परियोजना क्रियान्वरण में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि से रोकेंगे सट्टेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4%

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मकसद उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया, जो डेरिवेटिव बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा गंवा रहे थे। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, विकल्प सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। अब तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1% और विकल्प कारोबार पर 0.125% था।

बजट के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार वायदा-विकल्प कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा कि यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है। सबी के अध्ययनों के अनुसार, एफएंडओ खंड में 90% से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस खंड में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह निकट अविधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।

सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने को एसटीटी बढ़ाया : राजस्व सचिव

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना और प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। एफएंडओ में सट्टेबाजी से छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से वायदा-विकल्प बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को संभालने के लिए है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस वृद्धि के बाद भी एसटीटी की दरें होने वाले लेनदेन की मात्रा की तुलना में मामूली रहेंगी।

एसटीटी वृद्धि से पूंजी बाजार पर बढ़ेगा दबाव, विशेषज्ञों ने जताई चिंता



नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार के लिए दबाव पैदा कर सकता है। एफडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक धीरज रेवेली ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रौपल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तेज वृद्धि



व्यापारियों, जोखिम प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य आमदनी अधिकतम करने से अधिक लेन-देन की मात्रा को नियंत्रित करना प्रतीत होता है, क्योंकि संगठनित आय लाभ को वायदा विकल्पों की कम मात्रा से संतुलित किया जा सकता है। परेल्डू क्रैक्रेज फर्म ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रौपल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तेज वृद्धि

(बायबैक) को पूंजीगत लाभ के रूप में मानने से एक सांकेतिक क्षतिपूर्ति मिलती है और दीर्घकालिक निवेशक विश्वास मजबूत होता है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने कहा कि बजट सट्टेबाजी पर रोक के लिए वायदा और विकल्प पर उच्च एसटीटी जैसे सुनिश्चित उपायों से वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ बनाता है। आनंद राठी वैल्थ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा कि एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन-देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बाजार में डेरिवेटिव लेन-देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।



यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट-2026



● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटती हुई है

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तत्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटती हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राशियों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायतित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़

रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी। बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में ग्लर्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक ग्लर्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कार्यालय
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में ग्लर्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026-27) : 2.69 लाख करोड़ (2025-26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण : 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायतित योजनाएं : 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से : 10,000-12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि : 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026-27) : लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025-26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों को इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।



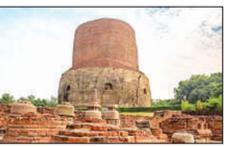
हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।



वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।



पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।



सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।



इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ: केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी से जुड़े कर्टम इयूटी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान स्फूर्ति से सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा

संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी- इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाट पाउडर, बैटरी स्कैप और अन्य क्रिटिकल मिनेरल्स पर बैसिक कर्टम इयूटी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट को कर्टम इयूटी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेन

रिव्हायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इन्फ्रस्ट्रक्चर से जुड़े उदाहरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैनुफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और वॉर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र को एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-को पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इन प्रावधानों से प्रदेश के

● लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर
● एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्कॉउंटिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कार्यालय का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत-विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि-तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए टोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक ग्लर्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टैम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी रिस्कल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य
अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है।

विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज
अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई-स्पीड रेल, आयुष, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

समझ से बाहर है बजट : अखिलेश
अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट-2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ बुनियादी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।

मायावती ने बजट पर उठाए सवाल
अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।

बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय
अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बजट सवालों से भागने वाला बजट है और सरकार को अब देश की जनता को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बजट में बेरोजगारी पर कोई टोस जवाब नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल
अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियादी को मजबूत करने का काम करेगा।

विश्लेषण बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मन-स्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य। हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग का राहत की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और

सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के टोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुरूप वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बड़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है

कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती

है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में

आत्मनिर्भरता की टोस जमीन तैयार करती है। उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह

सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।



प्रो. अजय द्विवेदी पूर्व डीन, रंधन संकलन और बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जौनपुर



अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।



अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियादी को मजबूत करने का काम करेगा।

बजट प्रतिक्रिया

वृद्धि, समावेशन का संयोजन वाला साहसिक बजट: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। मित्तल ने इसे विकास और समावेश को संयोजित करने वाला एक साहसिक बजट बताया और कहा कि कौशल विकास पर जोर के साथ विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में लगातार निवेश समय पर किया गया कदम है, जो धरोक्षताओं को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात की जगह धरोक्ष उत्पादन को बढ़ावा देगा। मित्तल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उपाय, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देना, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा।

यह बजट झुनझुना है दिखता है पर बजता नहीं: प्रमोद तिवारी

लखनऊ, एजेंसी। राजस्थान में उप नेता प्रतिक्रिया एवं सांसद प्रमोद तिवारी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह 'झुनझुना' की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन बजता नहीं। उन्होंने इसे किसान, बेरोजगार युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्योगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बजट से देश की जनता निराश हुई है। उनका दावा है कि बजट के बाद बाजार में गिरावट इसका संकेत है। नेता ने कहा कि पिछले एक वर्ष में पूंजी निवेश ठहरा हुआ है और न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न ही स्वदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू वर्ष में राजस्व प्राप्ति में 78,086 करोड़ रुपये और शुद्ध कर संग्रह में 1,62,748 करोड़ रुपये की कमी आर्थिक सुस्ती का संकेत है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में बजटीय कटौती की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस नई योजना या अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है और यह बजट केवल नारी तक सीमित है।

खेल विकास से सधेगी युवा शक्ति

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत

नई दिल्ली, एजेंसी

यूनियन बजट 2026-27 भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैनुफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने



के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीटों के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया

कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अलोक्य युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए,

बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा: केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज्ञान पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन



- 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज्ञान
- स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये

2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है।

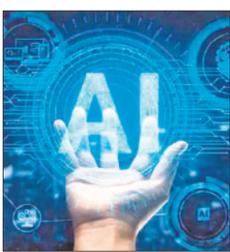
बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कॉचिंग और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।

भारत बनेगा एआई में सबसे बड़ा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत का एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों,



सामग्री का घेरलू विनिर्माण और डिजाइन और प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मजबूत समर्थन शामिल है-जिस 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है-जो भारत को वैश्विक एआई

हब के तौर पर स्थापित करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई और तकनीक को लेकर बजट में मिले प्रोत्साहन से देश में एआई-संबंधित बुनियादी ढांचे, डेटा-सेंटर, जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्षमता और शोध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीति के साथ एक वास्तविक और व्यावहारिक एआई विकास मॉडल तैयार कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा इंजन है, और भारत की रणनीति इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार एआई का उपयोग, स्किलिंग, रिसर्च और निवेश को समान रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा, स्टार्टअप्स तथा उद्योग सभी इस तकनीक का लाभ उठा सकें।

पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि परिवर्तनों का उद्देश्य कामकाज को आसान बनाना है।

रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास



● राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा

के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों

से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर-मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलूर, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगे और इनके आसपास नए रियल एस्टेट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भरोसेमंद, निवेश-अनुकूल और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करता है, जो भारत के शहरी और आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।

म्यूचुअल फंड आय से जुड़े ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी। आम बजट 2026-



27 के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर आगे बढ़ रहा है, जो जाएगी साथ ही, एक तन सीमा

तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है। यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। अब अगर निवेशक कर्ज लेकर निवेश करते हैं, तो उनके ऋण के ब्याज जैसे खर्चों को लाभांश या म्यूचुअल फंड आय से घटाया नहीं जाएगा। इससे ऐसी आय पर कर थोड़ा राशि प्रभावी रूप से बढ़ जाएगा।

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(G) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए



कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(G) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए

विदेश में रहने वालों को निवेश की होगी अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक

पीआरओआई निवेश

● भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे

उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा।

साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है। बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिशत पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

सुधार

बजट में प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 299 करोड़ खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी



देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। रविवार को पेश बजट के अनुसार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है। आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से,

120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगी' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को निर्धारित की गई है। मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है।

योग्यताओं से पर्याप्त रूप से अवगत कराने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम तथा मिड-करियर (कामकाज के दौरान) प्रशिक्षण सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस आवंटन में घरेलू या विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय स्ट्रेनोग्राफर सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क भी शामिल होगा। बजट दस्तावेज में कहा गया कि 52.2 करोड़ रुपये के आवंटन में सभी

के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। इसको आगामी वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी व्यय को 166.42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज में कहा गया कि इसमें सीएटी की विभिन्न पीठों के लिए भूमि को खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजी) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बजट समावेशी, वृद्धि और रोजगार बढ़ाने वाला: महेन्द्र देव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस महेन्द्र देव ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 समावेशी है और वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट कारोबारी सुगमता के साथ ही रहन-सहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। देव ने लिंकडइन पर पोस्ट किया, बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अगला कदम है। यह वृद्धि, समावेश और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए एक छूट, और कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

दुर्घटना दावे से मिला हर्जाना अब आयकर से मुक्त होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

- कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ
- एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

का प्रस्ताव है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को छूट दी जाएगी। यह संशोधन एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा उसके बाद के कर वर्षों के संबंध में लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

न्यूज़ ब्रीफ

अंतर्राष्ट्रीय काफ़ेस में आईएफटीएम की छात्रा सम्मानित

मुरादाबाद, अमृत विचार : आईएफटीएम विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय की बी. फार्मा. चतुर्थ वर्ष की छात्रा अनुश्री संजीवन ने गुरुकुल कागड़ी विवि हरिद्वार में आयोजित इंटरनेशनल काफ़ेस में उत्कृष्ट पोस्टर प्रस्तुतिकरण के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। काफ़ेस में देश-विदेश से लगभग 500 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। अनुश्री ने पोस्टर में नई दवाइयों की जांच के लिए जेब्रा फ़िश (जेब्राफ़िश) के उपयोग पर शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से दवाइयों की जांच वृद्धों और खरगोशों पर की जाती है, लेकिन उनकी सीमित उपलब्धता और अधिक लागत के कारण अब जेब्रा फ़िश पर शोध को अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। काफ़ेस में मलेशिया, न्यूजीलैंड (यूएसए) सहित कई देशों के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए और दवाइयों के उपयोग व अनुसंधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

बाल भिक्षावृत्ति बनी सामाजिक चुनौती

मुरादाबाद, अमृत विचार : शहर के चौराहों, बाजारों और मंदिरों के बाहर बाल भिक्षावृत्ति की समस्या लगातार बढ़ रही है। कम उम्र के बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, जो उनके भविष्य के लिए खतरा है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि गरीबी और परिवारों की मजबूती इसकी मुख्य वजह है। इसके बावजूद पुनर्वास और शिक्षा से जोड़ने की व्यवस्था कमजोर है। लोगों ने प्रशासन से बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

टीबी व एनीमिया जांच की धीमी रफ्तार

मुरादाबाद, अमृत विचार : सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी और एनीमिया जांच अभियान की रफ्तार शहरी क्षेत्रों में अपेक्षा अनुपम नहीं है। कई जगह नियमित शिविर नहीं लाए जा रहे हैं, जिससे मरीज चिन्हित नहीं हो रहे। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और जागरूकता के अभाव को बड़ी वजह बताया जा रहा है। समय पर जांच न होने से बीमारी गंभीर हो सकती है। लोगों ने अभियान को तेज करने की मांग की है।

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में कोविड व बजट से जुड़े प्रश्न पूछे

बायोमेट्रिक सत्यापन व सुरक्षा जांच के बाद 8,241 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : उग्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जिले में 28 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराई गई। परीक्षा के लिए कुल 12,480 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 8,241 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 4,239 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की कतारें लगी गई थीं। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, दस्तावेज जांच और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया अपनाई गई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। बागपत से परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी निखिल ने बताया कि



दयानंद कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर आते परीक्षार्थी।

● अमृत विचार

रीजनिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न थोड़े उलझाऊ थे, जिनमें समय अधिक लगा, जबकि सामान्य ज्ञान के प्रश्न अपेक्षाकृत सरल और सीधे थे।

लखनऊ से आए परीक्षार्थी मोहित और सतीश ने बताया कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कोविड-19 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे समसामयिक विषयों

से भी प्रश्न पूछे गए थे, जिससे तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिला। वहीं, बालामऊ से परीक्षा देने आए दीपक प्रजापति ने कहा कि प्रश्नपत्र में विलीय वर्ष 2025-26 के बजट से जुड़े सवाल भी शामिल थे, जो हाल की घटनाओं पर आधारित थे। अधिकांश अभ्यर्थियों का मानना

● 28 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा परीक्षार्थी बोले उम्मीद से आसान आया पेपर

करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन पढ़ने का मिला फायदा

जिन उम्मीदवारों ने नियमित रूप से करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की तैयारी की थी, उनके लिए पेपर ज्यादा कठिन नहीं रहा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने रात की सांस ली और परिणाम को लेकर बेहतर उम्मीद जताई।

था कि प्रश्नपत्र संतुलित था और उम्मीद से आसान रहा।

बैलगाड़ी पर पलटा दवा लदा केंटर, चार बैलों की मौत



सड़क पर बिखरे दवा के पैकेट।

● अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गलत दिशा में चलने से हुआ हादसा

अमृत विचार : दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रविवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रिवर साइड इन होटल के सामने दवाइयों से लदा एक केंटर रॉन्डा साइड से आ रही बैलगाड़ी पर पलट गई। हादसे में केंटर के नीचे दबकर चार बैलों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद केंटर चालक-परिचालक और बैलगाड़ी चालक-परिचालक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बैलों को निकालने के लिए दमकल टीम और दो हाइड्रा मशीनें बुलाई गईं। लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केंटर को हटाया जा सका, लेकिन तब तक चारों बैलों की मौत हो चुकी थी। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह लगभग चार बजे हुई। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर बैलों को निकाला गया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस फरार केंटर चालक-परिचालक और दोनों बैलगाड़ी के चालक को तलाश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केंटर चालक पानीपत का निवासी बताया जा रहा है। केंटर हिमाचल से पश्चिम बंगाल के गुवाहाटी जा रहा था।

गोवंश से भरे वाहन को न रोकने पर भड़के कार्यकर्ता

संवाददाता, विलासपुर

अमृत विचार : हाईवे पर गोवंशीय पशु लेकर जा रहे एक वाहन को वहां तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा न रोकने से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नाराज हो गए। बाद में कोतवाली पहुंचकर शिकायत करने पर प्रभारी निरीक्षक ने आश्वासन देकर शांत कराया।

गांव मुशरफ गंज स्थित गौशाला के प्रबंधक ओमप्रकाश आर्य के अनुसार बीते शनिवार को पेटल चौक के पास एक वाहन में संदिग्धवास्था में उन्हें गोवंशीय पशु जाता दिखा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से वाहन को रोककर जांच करने की मांग की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कोतवाल का

शिकायत करने पर प्रभारी निरीक्षक ने आश्वासन देकर शांत कराया

आदेश न होने की बात कहकर वाहन को जाने दिया। बाद में वह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह से बात की। बाद में प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया, कि किसी भी गोवंशीय पशु का गैर-कानूनी व्यापार, अवैध परिवहन या वध होने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर सुनील गुप्ता, प्रदीप गंगवार, दयाराम लोंधी, विपिन सैनी, अंकुश देवल, छोटू यादव, नन्हे कश्यप, बुद्ध यादव आदि शामिल रहे। उधर, प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि क्षेत्र में गोवंश की हर संभल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

सामाजिक समरसता का आधार है पंच परिवर्तन का सिद्धांत

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन हिंदू सम्मेलन समितियों एवं आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में महानगर में रविवार को जगह-जगह हुए। सभी जगह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

अजुन नगर (सिंडिकेट बैंक परिसर) में आयोजित सम्मेलन में क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीराम ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद हिंदू समाज के विघटन की परिस्थितियां बनीं, जिनमें डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर समाज को दिशा दी। गंगा मंदिर में महानगर शहर कार्यवाहक प्रमोद



गंगा मंदिर में हिंदू सम्मेलन में बोलते महाराज धीरशांत दास।

● अमृत विचार



हिंदू सम्मेलन में मंच पर उपस्थित अतिथि।

● अमृत विचार

महानगर में जगह-जगह हिंदू सम्मेलन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

जोशी ने संघ की सौ वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए 1947 के देश विभाजन, गोवा मुक्ति आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, रामसेतु आंदोलन और विभिन्न सामाजिक संघर्षों का उल्लेख किया। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने पंच परिवर्तन विषय पर कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य पंच परिवर्तन को व्यवहार में उतारना है।

चीन-पाक युद्धों में स्वयंसेवकों के योगदान को सराहा

बुद्धि विहार की शाहपुर बस्ती स्थित एक बैंकवेट हॉल में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आरंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। किडस वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि जीके पब्लिक स्कूल ने देशभक्ति से ओतप्रोत कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. हरपाल सिंह ने की। इस अवसर पर डॉ. अनिल जायसवाल, जयवंद, महावीर, सुखलेश, भूपेंद्र, विक्रम, प्रान्शु, प्रदीप गिरी और डॉ. पीतांबर सिंह सहित कई लोग रहे। महानगर सह प्रचार प्रमुख राजेश तोमर ने संघ पर लगे प्रतिबंधों और चीन-पाक युद्धों में स्वयंसेवकों के योगदान पर कहा कि इसी सेवा भावना के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की परेड में संघ स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। मेजर डॉ. मीनू मेहरोत्रा ने हिंदुत्व की विशेषता, वर्तमान चुनौतियां और समाधान पर विचार रखे। इस मौके पर अरविंद अग्रवाल, सनी सिंह, अवधेश पाठक, साकार भटनागर, दिनेश प्रजापति आदि रहे।

उन्होंने पारिवारिक एकता, सामूहिक भव' व पर्यावरण संरक्षण पेड़ लगाओ, पर जोर दिया। साथ ही स्वदेशी भाव भोजन, सामूहिक पूजा, 'अतिथि देवो पानी बचाओ और प्लास्टिक हटाओ को अपनाने का आह्वान किया।

सामूहिक विवाह: गड़बड़ी पर दो अफसरों का रोका वेतन

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कुछ पूर्व में ही विवाहितों की शादी कर योजना का लाभ लेने की शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। इसके तहत मुरादाबाद में चार दिसंबर 2025 को पांच दिसंबर 2025 को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित जोड़ों में से 10 प्रतिशत का

सामूहिक विवाह योजना में शामिल जोड़ों का होगा सत्यापन

कुंदरकी व मूढापांडे में 100 प्रतिशत जांच के निर्देश

सत्यापन कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मुगाली अविनाश जोशी ने बताया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सहित अन्य जनपदीय अधिकारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यापन आख्या तीन फरवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण

अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। वहीं, विकास खंड कुंदरकी एवं मूढापांडे में योजना के तहत कन्याओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री प्राप्त न होने की शिकायतें विभिन्न स्तरों से मिलने के बाद वहां शामिल सभी जोड़ों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के उद्देश्य से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मूढापांडे विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी प्रशांत

सिंह तथा कुंदरकी विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही दोनों कर्मचारियों के वेतन आहरण पर भी रोक लगा दी गई है। जिला विकास अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को भी जांच कर दो दिन में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी पंचुरी जैन ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

... मैं अपने देश की मिट्टी पर नाज करता हूँ



मुशायरा का दीप जलाकर आरंभ करती जिला पंचायत अध्यक्ष शोफाली सिंह व अन्य।

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

भारतीय सूफी फाउंडेशन की ओर से ऑल इंडिया मुशायरा

अमृत विचार : भारतीय सूफी फाउंडेशन के तत्वावधान में फलाहे दारैन इंटर कॉलेज में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन हुआ। मुशायरे की शमा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। शमा रोशन करने वालों में मुफ्ती दाशिरा उल कादरी, वैष्णवाचार्य धीरशान्त, सरदार गुरविंदर सिंह, पास्टर अरुण मासी और बाबा नूर शाह वारसी शामिल रहे। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शोफाली सिंह रहीं।

मुशायरे में देश के विभिन्न हिस्सों से आए शायरों ने राष्ट्रवाद, शहादत, भाईचारे और वतन से मोहब्बत पर आधारित कलाम पेश कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। रिफात मुरादाबादी ने देश की मिट्टी से वफादारी पर नाज जताया, वहीं शकील जमाली ने कुर्बानों के जन्मे से आजादी की अहमियत को बयान

महिला समेत तीन तस्कर दबोचे, 26 किलो गांजा बरामद

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : थाना नागफनी पुलिस ने मादक पदार्थों की महिला समेत तीन अभियुक्तों को 26 किलो 380 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि गांजा पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार से लाकर मुरादाबाद के बंगला गांव में देना था।



पुलिस की गिरफ्त में तस्कर।

रविवार को थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार को गश्त के दौरान अभियुक्तों में मफीजुल रहमान निवासी जिला कूच बिहार (पश्चिम बंगाल), अमरित निवासी जिला मुजफ्फरनगर और सोनम निवासी जिला मेरठ को 26 किलो अवैध माइक पदार्थ के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से बड़ी मात्रा

तलाश गश्ती

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किमिनल अपील सं. 2976/1987 में मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृजमोहन पुत्र केशो सिंह उम करीब 55 वर्ष निवासी कन्या व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद की तलाश की जा रही है जो पूर्व में कन्या पाकबड़ा में रहते थे वर्तमान में सपरिवार कहीं चले गये हैं जिनके सम्बन्ध में आसपास के लोगों एवं रिश्तेदारों से जानकारी करने पर पता नहीं चल पा रहा है।

अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि बृजमोहन पुत्र केशो सिंह निवासी पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद के सम्बन्ध में श्री विनीत कुमार मो. 7906738422 से अवगत कराने की कृपा करें

हुलिया : बृज मोहन, उपरोक्त उम्र करीब 55 वर्ष, रंग सांवला, नाक-कान, कद औसत

रोहेलखण्ड कैंसर इंस्टीट्यूट, बरेली

कैंसर की संपूर्ण देखभाल एक ही छत के नीचे

200 Bed का Cancer अस्पताल

अब आपके शहर के बीच में

के उपलक्ष में 4 फरवरी को मुफ्त परामर्श

स्तन कैंसर की जाँच (Mammography) मात्र 200/- में

बच्चेदानी के कैंसर की जाँच मात्र 100/- में

रेडियोथैरेपी के लिए ट्यूबीम एसटीएक्स (लीनियर एक्सलरेटर)

High Definition MLC, SRS, SBRT, IMRT, IGRT, Rapid ARC, RGSC, VMAT, 3D CRT, 6D Couch, 3 Energy Phototherapy, 5 Energy Electron Therapy

बरेली का एकमात्र PET CT कैंसर की स्टेज जानने लिए

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

हमारी सेवाएं

- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी
- रेडिएशन ऑन्कोलॉजी
- डे-केयर कीमो थेरेपी
- इन्यूनोथेरेपी
- कैंसर आई.सी.यू.
- फ्रोजन सेक्शन और इन्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री
- मैमोग्राफी
- कैंसर के रोकथाम की ओपीडी
- टर्मिनल कैंसर मरीजों की देखभाल
- इण्टरवेंशनल रेडियोलॉजी

रोहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कैम्पस, नजदीक सुरेश शर्मा नगर, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली उ.प्र.-243006

हैल्पलाइन: 7891235003, पेट सीटी बुकिंग के लिए +91 9811187117, आपातकालीन-9258116087

www.rohilkhandcancerinstitute.com

follow us on

/rohilkhand cancer institute

न्यूज़ ब्रीफ

शिक्षा को नवाचार व रोजगार से जोड़ेगा केंद्रीय बजट

मुरादाबाद, अमृत विचार : अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि यह बजट शिक्षा को डिग्री-केंद्रित ढांचे से आगे बढ़ाकर अनुसंधान, कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक है। विद्यालयी शिक्षा के लिए 83,561.41 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 55,724.54 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में एबीजीसी कंटेंट लेब्स, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गार्स हॉस्टल, मेडिकल सिटी से वृद्धि और शिक्षा-रोजगार समन्वय जैसी घोषणाओं को सराहनीय बताया गया है। महासंघ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहयोग दिए जाने की अपेक्षा भी जताई है।

आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दर्शाए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है, जो निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखता है। मोदी सरकार ने लेवेलुआ-संसाधन की बनाया आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना है। आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप के कारण भारत निरंतर लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त कर रहा है। - रामवीर सिंह, भाजपा विधायक, कुंदरकी

वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को अग्रगण्य और अपेक्षा से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। इस बजट में 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दर्शाए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है, जो निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखता है। मोदी सरकार ने लेवेलुआ-संसाधन की बनाया आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना है। आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप के कारण भारत निरंतर लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त कर रहा है। - रामवीर सिंह, भाजपा विधायक, कुंदरकी

वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को अग्रगण्य और अपेक्षा से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। इस बजट में 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दर्शाए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है, जो निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखता है। मोदी सरकार ने लेवेलुआ-संसाधन की बनाया आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना है। आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप के कारण भारत निरंतर लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त कर रहा है। - रामवीर सिंह, भाजपा विधायक, कुंदरकी

वित्तमंत्री के पिटारे पर थीं नजरें, टीवी व मोबाइल से चिपके रहे लोग

केंद्रीय बजट: महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय न होने पर मध्यम और निम्न आय वर्ग दिखा मायूस, अन्य ने बजट को सराहा

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : संसद में एक तरफ जहां केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत कर रही थीं तो वहीं दूसरी ओर हर वर्ग की नजरें उनके पिटारे से निकलने वाली सौगातों पर टिकी थीं। हर वर्ग को उनसे अपने लिए बेहतरीन की आस थी तो जिंदगी की गाड़ी सूचार्थ रूप से बढ़ाने की उम्मीद भी टिकी थी। वित्तमंत्री के मुंह से निकलने वाले हर शब्द लोग गौर सुन रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर हर वर्ग के बेहतर इलाज के लिए की गई घोषणाओं को सराहना मिली। तो महंगाई पर नियंत्रण के लिए बहुत ठोस उपाय न होने पर मध्यम और निम्न आय वर्ग को मायूसी भी मिली। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने बजट को निराशाजनक बताया। कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई और न इनकम टैक्स स्लैब ही बढ़ाया।

हालांकि कुछ लोगों ने बजट को हर वर्ग के लिए विकासमूल्य बताया तो बहुत तो बहुत ने बजट के प्रावधानों को कुछ खास वर्ग के हित में बताया। बजट के अनुसार आयुर्वेद को और ज्यादा प्रमाणिक और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे देश को कुशल वैद्य, शोधकर्ता और हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलेंगे। गुजरात के जामनगर में स्थित डल्लूयूएचओ के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का भी ऐलान किया गया है। इस कदम से भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग और यूनानी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और मजबूती मिलेगी। हेल्थकेयर पर विशेष नजर बजट में रही। सरकारी कर्मचारी जरूर मायूस हुए। आम जनता की बजाय चंद खास वर्गों के हितों को साधने वाला है। महंगाई लगातार बढ़ने के बावजूद रोजगार की जरूरतों पर बोझ कम करने के उपाय किए गए। जहां एक ओर अमीर वर्ग के व्यापार, निवेश और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को कई प्रकार की छूट दी गई, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे युवाओं व मध्यम वर्ग के लिए बजट में कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। यह बजट आम आदमी की उम्मीदों की थाली को भरने में पूरी तरह विफल रहा है। - जयवीर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी

वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को अग्रगण्य और अपेक्षा से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। इस बजट में 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दर्शाए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है, जो निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखता है। मोदी सरकार ने लेवेलुआ-संसाधन की बनाया आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना है। आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप के कारण भारत निरंतर लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त कर रहा है। - रामवीर सिंह, भाजपा विधायक, कुंदरकी



कोर्ट रोड स्थित दुकान पर टीवी पर बजट देखते लोग।

बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश, शिक्षा से व्यापार तक बड़े प्रावधान

मुरादाबाद, अमृत विचार : केंद्र सरकार ने बजट में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का बजट है। बजट में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए विद्यालयों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, छात्रवृत्ति योजनाओं और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, मुक्त जंच और इलाज, दवाओं की उपलब्धता व मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए प्रावधान किए गए हैं।

10 हजार करोड़ के निवेश से बायो-फार्मा शक्ति योजना चलेगी। जो भारत को वैश्विक हब बनाएगी। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत बढ़ेगी और तीन नए आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। एक लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रशिक्षित होंगे। - डॉ. आशीष कुमार सिंह

महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नियुक्ति सराहनीय है। - प्रियंका अवस्थी, गृहणी

खेल क्षेत्र में स्टैडियमों के विकास, खेल आकाशमयों, प्रशिक्षण, खेल छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं। खेल उपकरण सस्ते होने से खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। इससे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। - शिवम कुमार, क्रिकेट कोच

नई युनिवर्सिटी टाउनशिप में खेल सुविधाएं शामिल, एट्रोपॉलिटन से टेलीकॉम से वैज्ञानिक खेलों को बढ़ावा। खिलाड़ियों को विश्वप्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद करेगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा से आयुर्वेद शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को नई दिशा मिलेगी। - डॉ. मोहम्मद जावेद, लालपुर गम्बारी

रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये जारी किया है, जो पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि सामान्य वार्षिक बढ़ोतरी के औसत से कहीं अधिक है। रक्षा आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय को 1.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। - प्रो. आनंद कुमार सिंह, प्रभारी, रक्षा एवं स्वातंत्र्य अध्ययन, हिंदू कॉलेज

सरल इनकम टैक्स फॉर्म, विदेश यात्रा एवं शिक्षा से जुड़े खर्चों पर कर में दी गई राहत स्वागतयोग्य कदम है। बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक दिखाई देता है, जिससे छोटे एवं मध्यम उद्यमों को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा छोटे किसानों के साथ-साथ छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों पर कर्तव्य नैतियों आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। - डॉ. पवन कुमार जैन, महासचिव, व्यापार भारती

बजट में सरकार ने कृषि में विधिवत उस्तादकता बढ़ाना और उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, काजू, अखरोट आदि पर ध्यान देने को कहा है। इसका उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों की आय बढ़ाना है। उनकी कमाई को स्थाई रूप से सुधारना है। अच्छा बजट है। - कुलदीप दाऊर, किसान

हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर अहम घोषणा स्वागत योग्य है। बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने, डॉम सेंटर में सुविधाओं व संस्था बढ़ाना इलाज को मजबूत करेगा। मजबूत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर न केवल इलाज को पेश्वे बढ़ाता है, बल्कि समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा से आयुर्वेद शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को नई दिशा मिलेगी। - डॉ. मोहम्मद जावेद, लालपुर गम्बारी

वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं भारत को 2047 तक हम ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। ईएलएस पीएलआई को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव अच्छा प्रयास है। - डॉ. राजीव कुमार, शिक्षक

यह बजट अर्थ से समाज तक, अंत्योदय से अभ्युदय तक और साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट सिर्फ एक साल की योजना नहीं, यह 2047 के विकसित भारत की दृष्टि है। देश की 140 करोड़ जनता के लिए यह नूतन, जनिहोषी और विकासमूल्य बजट सरकार ने दिया है। - आकाश कुमार पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष

बजट में न तो आम जनता के लिए कुछ है न ही कर्मचारियों के लिए। रेल कॉरिडोर की घोषणा 20 प्रतिशत अभावग्रस्त वर्ग के लाभ के लिए की गई है। 180 प्रतिशत आम जनता के लिए शाल ट्रेनों के चलाने की कोई योजना नहीं दिखी। सरकारी कर्मचारियों आकर सीमा में बढ़ोतरी व पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को लेकर आशा निराश है, लेकिन कर्मचारी हितों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ तक नहीं। कुल मिलाकर बजट बेहद निराशाजनक रहा। - सुधीर पाठक, जिला प्रवक्ता कांग्रेस

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि पिछले साल इसे बदला गया था। बजट एग्जेंस है न किसी को नुकसान न फायदा, अच्छा बजट पेश किया गया। हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। - राजबहादुर सिंह, बैंक कर्मचारी

सर्कारी कर्मचारियों की आशा पूरी नहीं की गई। बजट शासकीय सेवकों के लिए निराशाजनक है। बजट में अपीएस की व्यवस्था नहीं है। जबकि यह बहुत पुरानी मांग है। कर्मचारियों को सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीम चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब भी नहीं बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष 12 लाख का इनकम टैक्स स्लेब सरकार पीट थपथपा रही है, जबकि 1 जनवरी 2026 से 88वां पे स्केल भी लागू हो जाना चाहिए था। जब 88वां पे स्केल लागू होगा तो कर्मचारियों के पे स्केल बढ़ेंगे जिसमें 12 लाख इनकम टैक्स स्लेब पर कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा। यह व्यवस्था 15 लाख पर की जानी चाहिए थी जो नहीं की। - गोपीकृष्ण, प्रांतीय कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ

इस बजट में डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति पर फोकस सराहनीय है, इससे ग्रामीण और मध्यम वर्ग के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ने से पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। - अभिषेक पाल, युवा

आर्टिफिशियल और इंधन से नौकरियां सृजित होगी। 17 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 25,000 किमी हाईवे और एबीजीसी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईएम के शॉर्ट कोर्स और जॉईंट क्रिएटर योजनाएं युवाओं को सशक्त बनाएंगी। - अशीष यादव, युवा

भाजपा सरकार ने इस बार भी बजट में निराशा किया। बजट में न आम जनता का क्रिक है न क्रिक। महंगाई बेताशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना टैक्स-शोषण है। अमीरों के काम-कारोबार और भूमि-फिरने पर दस तरह की छूट दी गई है लेकिन बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। - धर्मद यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा सेना

मध्यम वर्ग के लिए नहीं यह बजट पैसे वालों के लिए है। पैसे वाले और पैसे वाले हो जायेंगे। मनरेगा का नाम बदलकर धोखा किया गया है। मध्यम वर्ग को रखाई सरता होने की उम्मीद थी। इस वक्त जो देश के हालात हैं उससे देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। शेर बजाज के हालात भी ठीक नहीं है सोना चांदी के पैस धरने से कारोबार में लोगों को धोखा देना होगा। बजट में पैसा कुछ नहीं जिसकी प्रशंसा की जाए। - विनोद गुप्ता, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी

क्रियाशील गो-आश्रय स्थलों के नोडल अधिकारियों की सूची जारी

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : जनपद में गो-संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा क्रियाशील समस्त स्थायी, अस्थायी एवं कान्हा गो-आश्रय स्थलों के लिए नोडल अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची विभिन्न तहसीलों व विकास खंडों में संचालित गो-आश्रय स्थलों के प्रभावी संचालन एवं निगरानी के लिए तैयार की गई है।

गो-आश्रय स्थलों के प्रभावी संचालन एवं निगरानी के लिए की गई तैयारी

रविवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सुनील दत्त प्रजापति ने बताया कि भोजपुर, मूंढापांडे, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुरद्वारा, डिलारी, छजलैट, कांठ सहित जनपद के सभी विकास खंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में संचालित गो-आश्रय स्थलों के लिए जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इनमें जिला कृषि अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, नगर निकायों के अधिकांश अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने नामित गो-आश्रय

स्थलों का नियमित निरीक्षण करेंगे तथा गोवंश के लिए चारा, पानी, स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं में सुधार होगा और गो-संरक्षण कार्यों को नई गति मिलेगी।

कार्यालय संवाददाता मुरादाबाद

बजट से किसान मायूस, जताई नाराजगी

कार्यालय संवाददाता मुरादाबाद

अमृत विचार : प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से किसान धारा खसा मायूस नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि बजट में खेती-किसानी के लिए न तो कोई ठोस राहत दी गई और न ही उनकी प्रमुख मांगों को शामिल किया गया। रविवार को सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों को उम्मीद थी कि सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देगी और कृषि उपकरणों के साथ खाद-बीज पर भारी छूट का प्रावधान करेगी, लेकिन ऐसा न होने से निराशा व्याप्त है। नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। कर्मचारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। बड़े उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ किया जाता है, लेकिन किसानों की आर्थिक परेशानियों पर सरकार गंभीर नहीं दिखती।

किसानों ने कहा खेती के लिए बजट में कुछ भी नहीं

बजट 2026 में किसान खुश को टगा महसूस कर रहा है। किसानों की उरक कृषि यंत्र पर सॉल्यूडि बढ़ाना चाहिए थी साथ ही आयुष्मान योजना में प्रतिक्रिया को समितित करना चाहिए। आम जन से लेकर किसान मजदूर सभी वर्गों को निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साथ ही नौजवानों की कमाई मुक्त ऋण की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी। - महेंद्र सिंह रंधावा, भारतीय किसान यूनियन संघा

प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री अपने जनपदों को बढ़ा रहे हैं जबकि दोनों के लिए पूरे देश और प्रदेश की जनता एक समान है। कपड़े और सोना व चांदी पर दाम कम करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पैसे कम नहीं किए गए। यूरिया पर सॉल्यूडि है लेकिन वजन 50 किलो से 40 किलो कर दिया। जबकि यूरिया से किसानों को नुकसान है। वहीं डाई और फास्फोरस और कैल्शियम पर पैसे कम होने चाहिए थे। बजट से किसानों को कोई खास लाभ नहीं है। मोबाइल पर पैसे कम करने से खेती को कोई फायदा नहीं है। - डॉ. नीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैट

संत रविदास ने दी एकता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा

कार्यालय संवाददाता, मुरादाबाद

अमृत विचार : समाजवादी पार्टी के महानगर कैंप कार्यालय मकबरा फाटक पर रविवार को संत शिरोमणि रविदास व संत नरहरी दास (सोनार) की जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों संतों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने संत रविदास और संत नरहरी दास के जीवन, उनकी सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानवता के संदेश पर प्रकाश डाला। कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को एकता, सद्भाव और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी और संचालन डॉ. सोमवीर यादव ने किया। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, भाईचारे और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी

संत रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा आर्य समाज

मुरादाबाद, अमृत विचार : आर्य समाज स्टेशन रोड पर रविवार को साप्ताहिक यज्ञ व सत्संग आयोजित किया गया। पंडित वीरेंद्र आर्य ने वैदिक रीति से अरविंद आर्यवंशु की यज्ञमानी में यज्ञ कराया। शिवम आर्य ने ईश्वरीय भक्ति भजन प्रस्तुत किया। सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करते समाज के मंत्री रमेश आर्य ने बताया कि संत रविदास की जयंती हमें जहां विपरीत परिस्थितियों में साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने की शिक्षा देती है, वहीं कर्तव्यनिष्ठा का भी संदेश संत रविदास के कार्यों से मिलता है। उनकी जातिवाद की भावना को समाप्त करने की विचारधारा को आर्य समाज आज भी आगे बढ़ा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर आर्य समाज लातौर जातिवाद को समाप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सतीश चंद मदान ने भी इस अवसर पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रधान डॉ. अभय श्रोत्रिय, डॉ. आलोक कुमार, अरविन्द आर्यवंशु, मयंक आर्य, निर्मल आर्य, राकेश कुमार आर्य, रविंद्र आर्य, निपेंद्र आर्य, निहाल सिंह आर्य, रामपाल सिंह, दिनेश आर्य, रामपाल सिंह आर्य, सुनील कुमार, ज्ञान प्रकाश आर्य, अमित आर्य, खुशबू आर्य, सुमित आर्य आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राशिद हुसैन अंसारी महानगर अध्यक्ष, मजदूर सभा, सलीम वारसी, लालू परवेज़, शमशाद हुसैन अंसारी, शननू भाई साहब, मोहम्मद उमेर, शाहिद अली, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद सायफ, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद वसीम, असद खान, बिलाल मालिक, अरबाज फैसल, मोहम्मद शमशाद, मसरूर हसन, मोहम्मद शरीफ, फरमान खान, जुनेद आदि उपस्थित रहे।

सप्ताहिक यज्ञ व सत्संग में मौजूद आर्य समाज के लोग।

सपा के महानगर कार्यालय पर मनाई गई जयंती

उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का कार्य करती रहेगी। इसी अवसर पर संगठन को सशक्त करने के लिए महानगर अध्यक्ष ने वार्ड संख्या 45 के अध्यक्ष पद पर मोहम्मद उमेर को नियुक्त की घोषणा की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दीं। अंत में सभी ने संतों के आदर्शों पर चलने तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का संकल्प लिया।

संत रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा आर्य समाज

संत रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा आर्य समाज

संत रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा आर्य समाज

तड़के से शाम तक मौसम ने बदला मिजाज बारिश ने बढ़ाई परेशानी

मुरादाबाद, अमृत विचार : रविवार को मौसम ने दिनभर लोगों को अपने तेवर दिखाए। तड़के करीब तीन बजे अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसने नौद में खलल डाल दिया। रुक-रुक कर यह बारिश सुबह करीब साढ़े आठ बजे तक जारी रही। लगातार बारिश और उन्ही रुक के चलते सुबह के समय सर्दी का असर ज्यादा महसूस किया गया। सड़कों पर सननाटा पहरा रहा और जकारू जकारू से निकलने वाले लोग उड़ से बचाव के इंतजाम करते नजर आए। सुबह नौ बजे के बाद धूप निकली तो लोगों को कुछ राहत मिली।

सरकार एक तरफ तो मिलेट्स की खेती पर और जैविक खेती करने की बात पर जोर दे रही है, लेकिन सरकार के बजट में खेती-किसानी को ही अपेक्षित किया जा रहा है। किसान को साधारण खेती ही महंगी पड़ी रही है जबकि जैविक खेती में किसानों की लागत दो गुना और पैदावार कम होती है। ऐसे में किसानों को उचित किया गया है। - चौधरी नितिन सहरावा, महानगर प्रमुख सचिव, किसान यूनियन टिकैट।

बजट उम्मीद के पूर्णतया अनुपम नहीं है। हमें उम्मीद थी कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को थोड़ा और छूट देगी लेकिन पूर्व की भांति टैक्स स्लैब बरकरार रखी। पुराने टैक्स स्लैब में भी कोई छूट नहीं बढ़ाई गई। डॉलर की कीमत सातवें आसमान पर है। विदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। - सैयद आसिफ हसन, मंडलीय अध्यक्ष युवा एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन

न्यूज़ ब्रीफ

तेंदुए ने बकरी को बनाया निवाला

डिलारी, अमृत विचार : गांव राजपुर केसरिया में तेंदुआ एक किसान की बकरी को उठा कर ले गया। गांव निवासी महबूब शाम के समय में परिवार के साथ बैटकर खाना खा रहा था। थोड़ा अंधेरा होने पर तेंदुआ उसकी बकरी को उठा ले गया। किसान के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र हो गए महिला पुरुष हाथों में लाठी डंडे लेकर दौड़े। इसके अलावा गांव मलकपुर सेमली में तेंदुआ घूमता देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने खेतों में तलाश किया। दहशत जदा ग्रामीण राते जाकर गुजर रहे हैं और टोलिया बनावक पहरेदारी करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने तेंदुआ पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।

ट्रेन से कटकर युवक की मौत

अगवानपुर, अमृत विचार : नगर के मोहल्ला दाप निवासी मुनीष सैनी को परिवार वाले खोज रहे थे। रिवार को परिवार वाले पुलिस चौकी पहुंचे तब पता लगा कि रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति कटा है जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। परिवार वाले पीएम हाउस पहुंचे जहां मुनीष सैनी का शव देख परिवार में कोहराम मच गया। मनीष की 17 फरवरी को शादी होना थी।

विधि विधान से की शनि देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा



शनि देव की मूर्ति लिए श्रद्धालु।

संवाददाता, कांट

अमृत विचार : कांवड़ पथ पर मौड़ी हजरतपुर स्वामी देवानंद देव स्वरूप निष्कलंक महाराज जी के आश्रम में शनि देव मंदिर में शनि देव महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शनि देव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आचार्य मोहित की टीम द्वारा विधि विधान के साथ कराई गई जिसमें मुख्य यजमान निपेंद्र कसाना एवं उनके स्वजनों द्वारा यज्ञ हवन शुरू

कराया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शनि देव मंदिर और आश्रम के पास देसी शराब अंग्रेजी शराब की तीन दुकानों को हटाने की मांग श्रद्धालु ब्रजराज सिंह, सूरज सिंह, आदेश कुमार, सतपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, दाताराम महाराज, दीपेंद्र कसाना, मोहित कुमार, ऋषि पाल सिंह आदि लोगों ने जिलाधिकारी और तहसील प्रशासन आबकारी विभाग के अधिकारियों से की है।

● अमृत विचार

न्यूज़ डायरी



हिंदू समाज की एकजुटता पर दिया जोर

कांट, अमृत विचार : नगर के महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मौड़ी हजरतपुर मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता बजरंग दल के शहर प्रांत संयोजक उपेंद्र मिश्रा ने हिंदू समाज की एकजुटता एवं युवाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक होने का आवाहन किया। मुख्य अतिथि स्वामी प्रणवानंद महाराज जी नेजातिवाद भेदभाव को समाप्त करने का आवाहन किया। संयोजक प्रमोद चौहान, कर्नल वीके सिंह अरविंद गुरुजी, अंकुश चौहान, मुकेश महेश्वरी, दशरथ बिश्नोई, अशोक चौहान पर्यावरण के प्रांत संयोजक युवा शक्ति से मनीष चौहान, गौ सेवा गतिविधि के विभाग संयोजक अमित कुमार, खंड कार्यवाह दीपक, सहखंड कार्यवाह अभिषेक, खंड संपर्क प्रमुख नितिन, खंड व्यवस्था प्रमुख जीवन, खंड बौद्धिक प्रमुख आलोक कुमार, सूर्य प्रताप सिंह काठौर बिश्नोई आदि मौजूद रहे। अमृतसा डा. दिग्विजय सिंह ने एवं संचालन सत्यवान सिंह राजपूत ने किया।

चौधरी उदय वीर सिंह प्राइम इपैक्ट अवार्ड से सम्मानित

बिलारी, अमृत विचार : चौधरी उदयवीर सिंह को दिल्ली में लोकल फॉर वोकल टैलेट प्रमोटर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्राइम इपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें अभिनेता विनीत मलिक ने दिया। चौधरी उदयवीर सिंह ने बताया कि उन्हें सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने और युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया गया है। चौधरी उदय वीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे प्रयास युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। जो लोकल फॉर वोकल अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हैं।

● अमृत विचार

शराबी पति से परेशान महिला ने दी तहरीर

टाकुरद्वारा, अमृत विचार : महिला ने अपने पति पर शराब के नशे में आए दिन मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। ग्राम करनावाला जब्ती निवासी स्वाति तहरीर में कहा कि उसका पति भानु प्रताप शराब व नशे का आदी है और घर खर्च के लिए कोई पैसा नहीं देता। घर में रखा सामान बेच देता है तथा आए दिन घर में तोड़फोड़ करता रहता है। पीड़िता का एक आठ माह का पुत्र है। 31 जनवरी की रात उसका पति शराब पीकर घर आया और गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर लात-धूसों से बेरहमी से मारपीट की और उसका सिर दीवार में मार दिया, जिससे वह घायल हो गई। जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताया।



शब ए बारात को लेकर थाने में की गई बैठक

पाकबड़ा, अमृत विचार : शबे बारात को लेकर रिवार को पाकबड़ा थाने में बैठक हुई। जिसमें थाना प्रभारी योगेश कुमार ने कहा कि शब ए बारात पर सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। अगर कोई भी माहौल खराब करते देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। इस अवसर पर शहर इयाम काजी शम्से आनम, यामीन पहलवान, दानिश मलिक, मोहम्मद हाशिम, दानिश उतक दादरी, सूफी मुजीब आलम, मोहम्मद रफी, आस मोहम्मद, मोहम्मद अली आदि मौजूद रहे।



जशरन-ए-दस्तारबंदी आयोजित

कुंदरकी, अमृत विचार : ग्राम जैतपुर पट्टी के मदरसा मदीनतुल उलूम में दो आलम कॉन्फ्रेंस और जशर-ए-दस्तारबंदी में मुफ्ती मोहम्मद इकबाल (मुरादाबादी), कारी शोषर बा (बरेली) और कारी मुनाजिर ने हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई एकता का पैगाम दिया। मुहम्मद अली (जैतपुर पट्टी) और मुहम्मद सैफ (सिसोना) कुरान हिफ्ज पूरा कर हाफिज बने। हाफिज खुश नूर रजा और हाफिज साकिर ने सम्मान किया। मदरसा सवर एम सज्जाद हुसैन, साहनावाज पटेल, फुरकान अंसारी, मुस्ताफा रजा अंसारी, सरफराज, ग्राम प्रधान जबार हुसैन समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे।

● अमृत विचार

संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने का किया आह्वान

धूमधाम से मनाई संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती, शोभायात्राएं निकालीं, जगह-जगह किया गया स्वागत

संवाददाता, कांट

अमृत विचार : नगर में धूमधाम के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्मोत्सव शोभायात्रा एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।

नगर में हर्षोल्लास के साथ संत रविदास जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। प्रातः काल हवन एवं पूजन का आयोजन किया गया। संत रविदास धर्मशाला पर विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि मौलाना असद एवं आचार्य भावेश शर्मा ने कहा कि संत रविदास ने संसार को भाईचारा और एकता का संदेश दिया। उन्होंने संसार को बताया कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता इसलिए सदैव परिश्रमी बने रहें। उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा को चरितार्थ किया। गोष्ठी में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा राज्यपाल सिंह प्रजापति, कमेट्री के अध्यक्ष पवन भारती, महासचिव धर्मपाल, परितोष भारतीय, अभिषेक



शोभायात्रा में शामिल झांकी।



ग्राम टाट में शोभायात्रा में निकली झांकी।



गांव राजपुर कला में रविदास जयंती पर शोभायात्रा निकालते अनुश्राई।

● विभिन्न ग्रामों में आयोजित किये जयंती कार्यक्रम

भारती, देवराज सिंह जाटव, बलवंत सिंह, जगदेव सिंह, हरपाल सिंह, ओम प्रकाश बौड़ आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी में गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह एवं संरक्षक सरदार कृपाल सिंह चढ़डा को सम्मानित किया गया। कमेट्री के अध्यक्ष पवन कुमार भारती ने सभी का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी का संचालन गौतम कुमार ने किया।

● अमृत विचार

इससे पूर्व तीन दिवसीय महोत्सव में शनिवार की रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ समाजसेवी हिमांशी चौहान ने किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ केनरा बैंक के मैनेजर सुबोध गौतम ने किया। सर्वप्रथम ग्राम महमूदपुर माफी की शोभायात्रा कांट के रविदास धर्मशाला पर पहुंची, जहां से कांट एवं महमूदपुर माफी की शोभायात्रा संयुक्त रूप से निकली। दोनों शोभा यात्रा रविदास मंदिर से मोहल्ला पट्टी वाला, उपदेश नेता का

● अमृत विचार

चौराहा, मुख्य बाजार, वैश्य बिश्नोई धर्मशाला, मुख्य हाइवे होते हुए अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में सबसे आगे घनश्याम सिंह पहलवान व्यायाम शाला के खिलाड़ी हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम राम नरेश यादव, चौकी इंचार्ज राहुल राघव, उपनिरीक्षक कमलदीप व संजीव कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ

संत रविदास जयंती पर अर्पित किए श्रद्धासुमन

टाकुरद्वारा, अमृत विचार : संत शिरोमणि रविदास जी की 649 वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। रिवार को नगर के अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ व बसपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संघ के संरक्षक व बसपा के जिला सचिव डॉ. रामपाल सिंह गौतम ने कहा कि संत रविदास एक समाज सुधारक एवं छुआछूत व जाति वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। संत शिरोमणि ने विश्व को मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश दिया। संत रविदास ने अपने जीवनकाल में हमेशा समाज सुधार व कुरीतियों को नष्ट करने के लिए कार्य किए। उन्होंने पूरे विश्व में सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित किया। शेर सिंह सागर, अजय कुमार, अमित कुमार, ईश्वर सागर, धर्मेंद्र कुमार, धर्मवीर सिंह, गोपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, बंदी, सुशील कुमार, विशाल, डॉ. संदीप कुमार, गौरव गांगर आदि मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के गांव राजपुर कला स्थित रविदास धर्मशाला से चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में रविदास जयंती पर एक शोभायात्रा निकली गई। शिवलाल सिंह, प्रीतम कुमार, जगजय सिंह, सुमित कुमार, बिजेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, माजू सिंह आदि मौजूद रहे।

विधि विधान से की शनि देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा

युवक को मंदिर पर बुलाकर की मारपीट

प्रधानाचार्य पर हमला करने के चार आरोपी गिरफ्तार

मदरसा में छात्रों को बांटीं डिग्रियां

कांट, अमृत विचार : युवक को मंदिर पर बुलाकर मारपीट कर घायल कर दिया।

थाना कांट क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुर चाऊ पुरा निवासी निखिल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा को 31 जनवरी को शाम 7:00 बजे ग्राम चक छवि निवासी प्रशांत शर्मा पुत्र सतेंद्र शर्मा ने फोन करके गांव में मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया। निखिल शर्मा मंदिर पर मिलने पहुंचा, तो प्रशांत व उसके तीन अज्ञात साथियों ने लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया एवं जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और जब हमलावरों को ललकारा तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल को लेकर परिजन थाना कांट पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेज कर तहरीर को आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

● अमृत विचार

● डॉ. अंबेडकर का चित्र फाड़ने का आरोप लगा की थी मारपीट

जिसमें प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। अन्य शिक्षकों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।

विद्या भारती से जुड़े शिक्षकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित लोगों ने बैठक कर पुलिस को निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। पुलिस ने प्रधानाचार्य की तहरीर पर सात नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुड़ेसरा गांव निवासी अरुण, नवनीत, निवकी और संजीव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को उपजिलाधिकारी टाकुरद्वारा के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



जशनेदस्तारबंदी कार्यक्रम में मौजूद मौलाना, उलेमा व छात्र।

संवाददाता, बिलारी

● मदरसा रजा ए मुस्तफा में दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन

हासिल करने पर बल दिया। मुफ्ती की डिग्री मोहम्मद शरिफ, मोहम्मद रिजवान, सैयद शारिक मियां, मोहम्मद अजरहर्दुइन मिस्वाही, नूर मोहम्मद, मोहम्मद राशिद, आफताब आलम, कारी की डिग्री मोहम्मद मुफ्ती गुलाम जिलानी, मुफ्ती जीशान मिस्वाही, कारी रईस अशरफ आदि ने तत्करी कर पांच वक्त की नमाज पढ़ने, युवाओं को दीनी तालीम

● अमृत विचार

वाजिद को दी गई। इसके अलावा हिफ्ज की डिग्री मोहम्मद तहजीब को दी गई। कार्यक्रम में मेहमाने खुसूसी मुफ्ती फैजान मियां रामपुर, मुफ्ती ए आज़म मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब तशरीफ लाए। कार्यक्रम में मौलाना अखलाक, हाफिज अली रजा, मोहम्मद इरफान, खलील नेताजी, मोहम्मद उस्मान रजा, मोहम्मद अखलाक इंजीनियर, शमशाद हुसैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को सदारत सैयद जाकिर मियां ने की।

उलेमाओं ने दीन व पाकीजगी का दिया पैगाम

संवाददाता, कांट

अमृत विचार : दीनी इजलास में बड़ी संख्या में उलेमा-ए-किराम और अकीदतमंदों ने शिरकत की। कार्यक्रम का मकसद दीन-ए-इस्लाम की तालीमात, अखलाक और पाकीजगी के पैगाम को आम करना रहा। इजलास में कुरआन-ओ-हदीसी की रोशनी में समाज को सही राह पर चलने की नसीहत दी गई।

मुख्य अतिथि खसूसी मुफ्ती तैहीद उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद ने कहा कि नवी करीम मोहम्मद ने फरमाया कि ए लोगों दूसरों के काम आने वाले बन जाओ। नजीबाबाद से आए मुफ्ती मोहम्मद इस्लामुद्दीन मजाहिरी ने कहा कि अल्लाह ए ताला ने हाफिज ए कुरान के लिए बड़ी कामयाबी रची है। हाफिज कुरान ऐसे याजिब हो चुकी होगी। अतरसा ने



कार्यक्रम में बोलते उलेमा।

● इजलास-ए-आम में उलेमा-ए-किराम और अकीदतमंदों ने की शिरकत

के मुफ्ती मोहम्मद अरमान ने कहा कि अल्लाह पाक है तो अल्लाह ए ताला चाहता है कि मेरे बंदे भी पाक साफ रहे। इगलास का आगाज कारी अब्दुल वासित मुताम्मिल मदरसा शाही मुरादाबाद की तिलावत से हुआ। अस्दारत मौलाना यामीन ने

बजट को सराहा, तो किसी ने बतौर नाकाली

संवाददाता, बिलारी

अमृत विचार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में रिवार को अपना नौवां बजट पेश किया। सुबह से ही बजट को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोग टीवी और मोबाइलों पर बजट को सुन रहे थे।

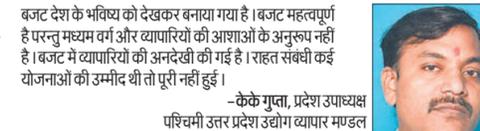
नगर में पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव के कार्यालय पर भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने बजट भाषण सुना। बजट में किसानों, पशुपालकों से लेकर वस्त्र परिधान और तकनीकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के कई एलान किए गए साथ ही कैंसर रोगियों के लिए कई दवाएं सस्ती की गईं। बजट को लेकर किसानों, नेताओं, व्यापारियों और राजनीतिक लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया रही।



बजट में सरकार ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। बजट कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बजट पूरी तरह से निराशापूर्ण है। मध्यम वर्ग के लिए राहत की कोई योजना नहीं है। -सौरभ यादव, सपा नेता



बजट सराहनीय है। शुगर और कैंसर को दवाई, किचूद के सामान सस्ते होंगे। इससे मरीजों को लाभ होगा वहीं बच्चों का भी विकास होगा। व्यापारियों को यह लाभ होगा की इनकम टैक्स में किसी छेटी गलती पर सजा नहीं होगी। -संजय जैन, नगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल



बजट देश के भविष्य को देखकर बनाया गया है। बजट महत्वपूर्ण है परन्तु मध्यम वर्ग और व्यापारियों की आशाओं के अनुरूप नहीं है। बजट में व्यापारियों की अनदेखी की गई है। राहत संबंधी कई योजनाओं की उम्मीद थी तो पूरी नहीं हुई। -केके गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, पश्चिमी उर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल

इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं ने सुना बजट भाषण

टाकुरद्वारा, अमृत विचार : इंटर कॉलेज में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजन आशुतोष अग्रवाल ने किया। बजट भाषण भी सुना गया। नगर अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र पाल, पंकज पाल, भूपेंद्र सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सूचना

थाना हयातनगर जनपद सम्भल पर दिनांक 17.10.2025 को वादी मुकाम श्री अकरम पुत्र मकबूल नि. मक भूड़ थाना हयातनगर जिला सम्भल द्वारा अभियुक्त रिक्त पुत्र तुलसी नि. ग्राम बवैना थाना हयातनगर जिला सम्भल द्वारा वादी की पुत्री कु. सोनम उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भाग ले जाने के सम्बन्ध में मु.अ.सं.-261/2025 धारा 1367(2)/87 बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जानकारी मिले या दिखाई दे तो थाने पर सूचना दी। पीड़िता/अपहता कु. सोनम का हलिया निम्न प्रकार है। हलिया : कु. सोनम पुत्री नि. ग्राम मकभूड़ थाना हयातनगर जिला सम्भल उम्र करीब 16 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, कपड़े ग्रे स्ट्रे, काले रंग की पजामी पहने है, चेहरा सामान्य है तथा नजर का चश्मा पहनती है। (सत्यविजय सिंह) अपराध निरीक्षक थाना-हयातनगर जनपद-सम्भल-7055124493 (अमेश सिंह सोलंकी) प्रभारी निरीक्षक थाना हयातनगर, जनपद सम्भल 9454404040, 8393030024

संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य के एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिए आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीना का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलौकिक कवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समन्धान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र-राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।



राजत मेहरोत्रा
वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6% के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को उधार लेना पड़ता है, तो उसे कम उधारा लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेंटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

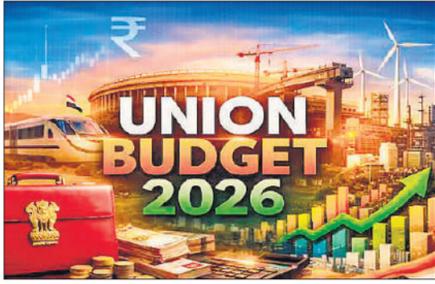
कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रारंभिकों को घटाकर 2% किए जाने से विदेशी निवेश करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभार्थी वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई प्रोथे फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है- असफलता का भय।

-पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

आम बजट 2026 विकास व अनुशासन का संतुलन



केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6% के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को उधार लेना पड़ता है, तो उसे कम उधारा लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेंटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रारंभिकों को घटाकर 2% किए जाने से विदेशी निवेश करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभार्थी वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात



रोहित माहेश्वरी
खतबे प्रवक्ता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए'। आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी है। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गाँविया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पढ़ाई के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पढ़ाई के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है। अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिकशा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह कक्षा के पढ़ाई के स्कूलों में दाखिला और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गाँविया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पढ़ाई के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पढ़ाई के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है। अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिकशा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रसंगवश

एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है। पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुए। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीढ़ित मानवता की पीढ़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प लिया। अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोह और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा। वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पिटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संस्था नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं। स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लाल देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वैश, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पद्मश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।

दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमें हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेंटल करा लें। सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटारसा तो यहीं रहेगा।

कोंग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छ' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

कहीं नहीं जाएंगे। -मदन दिलावर

शिक्षा मंत्री

कोंग्रेस नेता, राजस्थान

राजस्थान सरकार

सोशल फोरम

जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक में थे, कुछ खिलाफ। आखिर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे। 'मैं गुनहागर, रिंद, सियाहकार, बदनसीब और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।' अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आखिरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर खामोश हो गए। सिरहाने बातल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौका मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा गए। नात के मजबून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आखिर एक दिन नात का मतला हो गया। फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक सूखा नहीं था। धरत तो यह हाल था, दूसरी तरफ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आखिर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुताज़िज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!' इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मंच को ओर देखा और प्रेम से भर स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रसूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?' शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली- 'एक रिंद है और मदावत-ए-सुल्तान-ए-मदीना हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना -फैसबुक वॉल से

सामयिकी

बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं। फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं। जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यभार पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना। डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उदासियां उड़ाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियां की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटों को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।



अभिका अंबी
लेखिका

नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रेसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

इन कारों की मांग सबसे अधिक

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैनानआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।



पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वरंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रान्सफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के डेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारों खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर



Hero Vida Dirt .E K3: बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt .EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।



कीमत और उपलब्धता
Vida Dirt .EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

दमदार बैटरी

Dirt .EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटार कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

इंटरनेशनल पहचान

Dirt .E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt .EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

बच्चों के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।



सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

काम की बात

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ठंड का बाइक पर असर

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लोड-एंसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेटेनसेस नियमित नहीं होता।

स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके

- **स्पाइक प्लग की भूमिका अहम**- ठंड और नमी के कारण स्पाइक प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पाइक कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पाइक प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट प्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से घात पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड**- सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग**- कार्बोरेटर वाली बाइक में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकेंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजमेशन बढ़ सकता है।
- **इंजिन ऑफ रखकर प्री-किक तकनीक**- ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इंजिन बंद रखकर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान**- बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मंटेनेंस सलाह**- ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल**- ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कॉसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मंटेनेंस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



मॉय फर्स्ट राइड

सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा



जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई। 2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा। कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्ट्रीटिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सलेरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन

दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूँ और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूँ। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया। आज जब मैं कार चलाती हूँ, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

आम आदमी के लिए खास नहीं, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं

विपक्ष को रास नहीं आया बजट, बोले- आम जनता को कुछ नहीं मिला, रविवार को टीवी व मोबाइल पर बजट देखते रहे लोगे

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार : उद्यमियों सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार का बजट दूरगामी बताया है, जबकि विपक्षी बजट को दमदार नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार के 9वें आम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि विदेश यात्रा, कैसर की 17 दवाओं समेत, लिथियम बैटरी, कपड़ा, सीएनजी, माइक्रोवेव ओवन को सस्ता किया है। जबकि खनिज, स्क्रैप और शराब महंगी हुई है। डिफाल्टर आयकर करदाताओं के लिए सजा नहीं, बल्कि जुर्माने का प्रावधान किया है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं।

बजट में व्यवसाय क्षेत्र के लिए राहत है। छोटे उद्यमियों के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 10 लाख क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपये की सीमा तक जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए श्रद्धा गारंटी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई है। टीडीएस और टीसीएस दरों में राहत दी गई है। छोटे-मझोले आयकरदाताओं की सरलता के लिए आईटीआर रिवाइज की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। किसान आम लगा रहे थे कि किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ जाएगी जो पूरी नहीं हुई। हालांकि, आयात में टैरिफ 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मैनुफैक्चरिंग के 40 हजार करोड़ का प्रावधान व बायोगैस के दामों में कमी की गई है। चमड़ा, वस्त्र परिधान और लिथियम पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। गृहणियों को भी कोई राहत नहीं है। गैस के दाम, गरम मसाले, आटा, दाल के भाव जस के तस हैं। पेशा है सीए, उद्यमियों, नौकरोंपेशा, किसानों और गृहणियों से हुई बावतचीत के मुख्य अंश...

दरी के गोदाम से हजारों की चोरी

सैफनी, अमृत विचार : नगर के अकबरपुर मार्ग पर स्थित दरी के गोदाम से शनिवार की रात चोर दरवाजे की जाली तोड़कर नकदी समेत हजारों का माल समेत कर फरार हो गए। नगर के खेड़ा मोहल्ला निवासी रिजवान पुत्र हमीद का अकबरपुर मार्ग पर दरी का गोदाम है। शनिवार की रात चोर गोदाम के बरखर से निर्माण हो रहे मकान की बंध रही पाड़ के सहारे गोदाम में लगे लकड़ी के गेट पर लगी जाली को तोड़कर अंदर घुस गए। रिजवान ने बताया कि चोर गोदाम के अंदर लगे एक इनवर्टर दो बैटरी और काउंटर की दरजान में रखे 33 हजार की नकदी व दो कैमरे और डीवीआर सहित करीब 70 हजार रुपए का माल समेत कर फरार हो गए। रविवार की सुबह छोटे भाई निजाम ने गोदाम खोला तो चोरी होने का पता लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दे दी है।

सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई

सैफनी, अमृत विचार : नगर में शनिवार को प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। छितीनी मार्ग स्थित सरकारी जमीन गाटा संख्या 494 ख 27 हेक्टर (खर्रां भूमि) पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उक्त सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था और उस पर पक्के निर्माण भी कर लिए थे। हल्का लेखापाल राहुल कुमार ने बताया कि उपजिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस बल तैनात रही।



परिवार संग बजट देखते उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल।



एक कार्यालय में बजट देखते लोग।

केंद्र सरकार का बजट दूरगामी है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद थी लेकिन, बजट आते ही सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बजट में महंगाई रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है।

- अंकित कुमार, सीए

बजट शिक्षकों एवं वित्तभोगी वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। इस बजट में शिक्षक समाज को बिलुला था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर निर्णय लेकर इसे लागू जरूर करेगी लेकिन, ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

- अदुल रज्जाक खां, जिला मीडिया प्रभारी भाकियू अराजनीतिक

केंद्र सरकार ने बजट 2026 में किसानों को ऐसा कुछ नहीं दिया, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकेगी।

- हरीश अहमद, प्रदेश महासचिव, भाकियू टिकैट

लाल रस्तोगी दूरदर्शिता वाला बजट है, वर्तमान में ही बड़ी राहत देने वाला नहीं बजट नहीं है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए गए। इससे आम जनता को राहत मिलती है।

- छोटै लाल रस्तोगी, नगर अध्यक्ष उग्र उद्योग व्यापार मंडल

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देगा बजट: औलख

कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। रविवार को संसद में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को जानने के लिए भाजपाइयों में खासी उत्सुकता रही। जिसके चलते कैबिनेट कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई। स्क्रीन पर बजट भाषण का सीधा प्रसारण देखा। भाषण के दौरान वित्त मंत्री की कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर भाजपाइयों ने सराहना की। इस दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, अधोसंरचना एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने वाला सिद्ध होगा। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अंगनलाल राजपूत, राजेश सैनी, युवकीरत औलख, वेंतन पारुथी, सीध सक्सेना, किरनजीत कौर, अनुशुभा कश्यप, रीता गौतम, शमीम हसन, जसपाल सिंह, धारेलाल सैनी, रवि राठौर आदि मौजूद रहे।

को विशेष पैकेज देते हुए लोन की सीमा तीन लाख से बढ़ा कर पांच लाख कर दी। साथ ही कोको, काजू और चंदन की लकड़ी की खेती को बढ़ावा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बजट में बड़े उद्योगों पर टैक्स वृद्धि की गई है, इस कारण उद्योगों पर असर पड़ेगा कुल मिलाकर यह बजट सर्वस्पर्शी है। विकसित भारत

बजट में कैसर के मरीजों की 17 दवाएं सस्ती की गई हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर भेजे जाने वाले पैसे पर लगने वाला टैक्स 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। शैश्यों की खरीद-फरोख पर 0.02 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया गया है।

- सोरभ कुमार, सीए

बजट 2026 शिक्षकों और कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। बजट में पुरानी पेंशन पर कोई चर्चा नहीं हुई जबकि उम्मीद थी कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी। नई पेंशन बाजार पर आधारित है जिसमें उतार चढ़ाव स्वभाविक है।

- जगदीश पटेल, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

बजट 2026-27 से सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। बजट में कर्मचारियों की बुद्धि की लाठी पुरानी पेंशन बहाली नहीं की बात नहीं की गई है और न ही शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया है।

- डॉ. राजवीर सिंह जिलाध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक

बड़े उद्योगों पर टैक्स की वृद्धि की गई है, इससे व्यापार पर असर पड़ेगा। साथ ही व्यापारियों के विक्रित्सा बीमा योजना न लाने पर निराशा हुई।

- अनिल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उग्र उद्योग व्यापार मंडल

केंद्रीय बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। रोजगार सृजन से लेकर देश के दायित्व विकास और महंगाई नियंत्रण तक, यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आम आदमी के लिए यह बजट एक प्रकार से बरदान साबित होगा।

- हरीश गंगवार, जिलाध्यक्ष, भाजपा, रामपुर।

दीर्घकालिक 2047 के विजन को पूरा करता है। बजट सुनने वालों में जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल,

भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, नवाचार, स्टार्ट-अप और फौशल विकास पर फोकस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश से भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का प्रयास है। - प्रियंका शर्मा, बैंककर्मी

बजट देश के आर्थिक विकास को नई गति देने वाला, रोजगार के अवसरों का विस्तार करने वाला है। उद्योगों को प्रोत्साहन देकर निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, इससे लोगों को बत बढ़ेगी और विकास का संतुलित और दूरदर्शी दर्शन भी साकार होगा।

- डॉ. मारिया मसूद

कैसर की दवाओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। इससे कैसर रोगियों के तीमारदारों को खासी राहत मिलेगी। गरीब लोगों के हित में सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है।

- अवतार सिंह, अध्यक्ष वीर खालसा सेवा समिति

बजट शिक्षकों एवं वित्तभोगी वर्ग के लिए निराशाजनक है। आयकर सीमा में वृद्धि न किया जाना भी मध्यम वीर और वित्तभोगी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। शिक्षक समुदाय को पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीद थी, बजट में कोई घोषणा नहीं हुई।

- रवेन्द्र गंगवार, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ

बजट 2026 और 2027 पेश कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जबकि, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। सरकार अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है सरकार किसानों को समझने में सफल होना चाहती है कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं।

- भानु प्रताप सिंह गंगवार, किसान नेता

बजट पूरी तरह निराशाजनक है। इससे न तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और न ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बजट में किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ाई गई, व एम्प्लॉय को कानूनी गारंटी नहीं दी गई है। किसानों का ऋण भी माफ नहीं हुआ।

- पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाकियू अराजनीतिक

युवा जिलाध्यक्ष विपुल गुप्ता, नगर अध्यक्ष छोटे लाल रस्तोगी, युवा नागराध्यक्ष नवीन भाटिया, प्रशांत अग्रवाल, चिराम गर्ग, रमेश गुप्ता, किशन लाल शर्मा, रितेश यादव आदि मौजूद रहे।

सनातन संस्कृति श्रेष्ठ, बच्चों को दें संस्कार विविधता में है शक्ति



आदर्श रामलीला मैदान में हिंदू सम्मेलन में सम्मानित छात्राएं व मौजूद अतिथि।

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार: आदर्श रामलीला मैदान में रविवार को हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति और श्रीराम एवं गिरिधर बस्ती के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज द्वारा एक विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि अणुमानधाम, रामनगर के संस्थापक अध्यक्ष विजय भाटिया ने कहा कि हिंदू संस्कृति श्रेष्ठ है और बच्चों को अच्छे संस्कार दें।

विश्व में अनेक संस्कृतियां रही जो कालबाह्य होकर समाप्त या विलुप्त पर्याय हो गईं। परंतु सनातन संस्कृति अनादि काल से चली आ रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और विष्व कल्याण की कामना करने वाला केवल हिंदू चिंतन ही है। आज आश्रयकता है कि हम अपने अतीत को याद करें और संगच्छ्व संवदध्वं यानि

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार: ज्वालानगर के राम मनोहर लोहिया पार्क में रविवार को हिंदू सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कार्यवाह चंद्रपाल ने कहा कि समाज की शक्ति उसकी विविधता में है, लेकिन यह विविधता तभी सशक्त बनती है। जब उसमें एकता और परस्पर सहयोग हो।

कार्यक्रम का आरंभ मुख्यअतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कार्यवाह चंद्रपाल, जिला कार्यवाह पुनीत, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष रामसेवक शर्मा एवं कार्यक्रम अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आनंद कान्वेंट स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व फर्स्ट इंफ्रेशन स्कूल के बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाटक पेश किया।



राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित सम्मेलन में मौजूद लोग।

साइबर ने उगी के 45,000 रुपये वापस कराए

रामपुर, अमृत विचार: ज्वालानगर थाना सिविल लाइंस निवासी गौरव कुमार की पत्नी के बैंक खाते से 13 अक्टूबर 2023 को साइबर ठगों ने फर्जी एलआईसी एजेंट बनकर 45 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। यूपीआई के माध्यम से यह राशि उगी गई। साइबर फ्रॉड को लेकर उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी साइबर अपराध) के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल थाना सिविल लाइंस ने तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी को शत प्रतिशत राशि 45,000 रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराए।

साइबर सेल अधिकारियों ने बताया कि प्रलोभन में आकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपना खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नंबर आदि गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर पोर्टल पर शिकायत करें। 1930 पर कालं कर शिकायत दर्ज कराएं व थानों में स्थापित साइबर सेल पर संपर्क करें।

जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं



कार्यकर्ताओं से वार्ता करते पूर्व कैबिनेट मंत्री नकवी।

अमृत विचार: पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रविवार को रामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने व्यापार मंडल के महामंत्री कपिल आर्य के अजीतपुर स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं।

नकवी ने कहा कि व्यापार और व्यापारियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित भारत के सफल सफर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। आज वह 11:30 बजे बजट व अन्य

न्यूज़ ब्रीफ

वाहन की चपेट में स्कूटी सवार की मौत

बिजनौर, अमृत विचार : अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। थाना क्षेत्र के गांव गोहावर जैत निवासी रमेश कश्यप का पुत्र सुमित (26) शनिवार की देर रात स्कूटी पर देहरादून से गांव आ रहा था। नूरपुर-मुरादाबाद हाईवे पर अस्करीपुर में एक ईट भूँडे के सामने किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गया। पीएचडी पुलिस ने घायल सुमित को सीएचएस भिजवाया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रमेश की ओर से अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार युवक देहरादून में रहक मजदूर करता था।

खेत में मिला युवती का शव, पुलिस कर रही जांच

बिजनौर, अमृत विचार : थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव के खेत में युवती का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। गांव रावली निवासी विजयपाल सिंह की पुत्री पायल (18) का शव रविवार की सुबह एक खेत में पड़ा हुआ मिला। थाना प्रभारी सुमित राठी और सीओ सिटी संग्राम सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे तथा शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। लोगों को कहना है कि खेत के चारों तरफ बार है संभवतः उसमें करंट हो जिससे युवती की मौत हो गई हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष सुमित राठीने कहा कि जांच की जा रही है।

शार्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जला

सैदंगली, अमृत विचार : थाना क्षेत्र के गांव ढक्का मोड़ मोड़ निवासी इरफान पुत्र रईस अहमद के घर में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से फ्रिज, वाशिंग मशीन, सोफे और गैस सिलेंडर सहित अन्य घरेलू सामान जल गए। इरफान ने बताया कि वे परिवार समेत अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पानी की बरसे से आग का काबू पाया। इरफान के अनुसार, इस आगजनी में उन्हें डेढ़ लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।

संभल जा रही तेज रफ्तार डीसीएम पलटी

सैदंगली, अमृत विचार : संभल हसनपुर मार्ग पर ढक्का मोड़ गांव से शनिवार देर रात एक डीसीएम अनियंत्रित होकर यात्री शेंड और पुलिस बृहद से टकराकर पलट गई। तेज गति से संभल की ओर जा रही यह डीसीएम पशुओं के सींगों से लदी थी। सैदंगली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ गांव में वाहन अनियंत्रित होकर यात्री शेंड और बीपी पुलिस बृहद में जा घुसा और पलट गया। हादसे के बाद वाहनक डीसीएम को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

आम बजट: सरकार ने दीं कई योजनाएं फिर भी रह गई कुछ कमी

बजट में उद्यमों, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर कई योजनाओं की घोषणा, महंगाई को लेकर आमजन के हाथ लगी निराशा

कार्यालय संवाददाता, अमरोहा

अमृत विचार: केंद्र सरकार ने रविवार को अपना बजट पेश किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया है। इस बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने पूरी तरह से नकार दिया।

रविवार को जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो लोग टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर बैठ गए और बजट को ध्यान पूर्वक सुना। बजट में आम आदमी को कई तोहफे दिए। युवाओं, उद्यमियों के लिए भी एलान किए गए। बजट को लेकर व्यापारियों, शिक्षकों, युवाओं और आम नागरिकों की अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। तमाम लोगों का कहना है कि बजट में विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में इसका असर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देगा। व्यापारियों ने बजट में लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी गई राहत का स्वागत किया। शिक्षकों और अभिभावकों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत



टीवी पर बजट देखते व्यापारी।

● अमृत विचार

यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। नागरिक, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसरना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। - अभिनव कौशिक, जिला महामंत्री भाजपा

महंगाई कम करने युवाओं को रोजगार की कई व्यवस्था नहीं की गई है। व्यापारियों को कोई राहत नहीं है। किसानों की कर्ज माफी योजना की कोई व्यवस्था नहीं। गन्ने के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं इसलिए बजट पूरी तरह जन विरोधी है। किसान विरोधी है। बजट में देश की जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में सिर्फ घोषणाएं दिखाई दे रही हैं। बजट पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। - ओमकार कटारिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

करने से सरकारी विद्यालयों को लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ आम नागरिकों ने महंगाई और रोजगार की जरूरतों को लेकर बजट पर

चिंता जताई है। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे।



बजट का चित्रण करते चित्रकार जुहेब खान।

● अमृत विचार

बजट विकास और जनकल्याण को समर्पित है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए यह बजट कई उम्मीदें लेकर आया है। इससे उद्यमों को पंख लगेगी शिक्षा में और सुधार होगा। - राजीव तरार, विधायक मंडी धनौरा

बजट में शहरी सुविधाओं, स्वच्छता, सड़क, पेयजल और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यदि बजट की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया गया तो नगर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। - प्रवीण अग्रवाल, चेरमैन धनौरा

यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को स्थान में रखकर बनाया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। - राजपाल सैनी, अध्यक्ष नगर पालिका हसनपुर

केंद्रीय बजट देश के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप है, जो किसान, युवा, महिला, गरीब, मध्यम वर्ग और उद्योग-संघों के हितों को समान रूप से ध्यान में रखता है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक, डिजिटल कृषि को प्रोत्साहन देने के प्रावधान हैं। - डॉर हरि सिंह दिल्ली, शिक्षक विधायक

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरीके से पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों का बजट है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा छात्र, युवा, किसान एवं व्यापारियों के साथ धोखा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी बजट में नहीं है। महंगाई कैसे कम होगी इसके बारे में बजट में कोई रोडमैप नहीं है। - कमाल अख्तर, विधायक

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में 25000 रुपए प्रतिवर्ष करके राम जी योजना को खेती किसानों से मर्ज होने की उम्मीद थी। परंतु किसान आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार को किसानों के प्रति गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। करोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था केवल किसानों की जगह से ही बची थी। - चौधरी दिवाकर सिंह, अध्यक्ष भाकियू शंकर

शादी कराने का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपए की ठगी

संवाददाता ढबारसी

अमृत विचार: आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव तलाबडा निवासी युवक से एक महिला समेत तीन लोगों ने शादी कराने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की ठगी कर ली। जब युवक की शादी नहीं हुई तो रुपए वापस मांगे। ठगी करने वाले लोगों ने वापस करने से इंकार कर दिया। पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की। डिप्टी सीएम के निर्देश पर महिला समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला क्षेत्र के गांव तलाबडा का है। दरअसल गांव निवासी विजेन्द्र पुत्र महेश पाल मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहा था। लगभग एक वर्ष पूर्व भोजराज पुत्र मरठू व प्रीति पत्नी भोजराज ने कहा कि शादी करा देंगे जिसके लिए डेढ़ लाख रुपए

खर्च करने पड़ेंगे। विजेन्द्र ने लोगों से कर्ज लेकर डेढ़ लाख रुपए की व्यवस्था की। प्रीति ने अपने साथी व्यवस्था इस्लाम के खीते में डेढ़ लाख रुपए डलवा लिए। विजेन्द्र ने शादी कराने को कहा तो उपरोक्त लोगों ने 50 हजार रुपए और मांगे। विजेन्द्र ने और रुपयों की व्यवस्था न होने पर अपनी रकम वापस मांगी तो इन्होंने रकम देने से साफ इंकार कर दिया। विजेन्द्र ने इस घटना की सूचना 20 अप्रैल 2025 को आदमपुर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से शिकायत कर अपनी रकम वापस कराने तथा उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम के निर्देश पर आदमपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बजट को बताया लाभकारी, तो किसी ने कहा-ठीक नहीं

संवाददाता हसनपुर/मंडी धनौरा

अमृत विचार: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार नौवां बजट पेश किया है। बजट को देखने एवं सुनने की चाहत एवं बजट में आम आदमी के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया गया इसको जानने के लिए सुबह से ही लोगों में उत्सुकता थी और टीवी अर्थव्यवस्था न होने पर अपनी रकम वापस मांगी तो इन्होंने रकम देने से साफ इंकार कर दिया। विजेन्द्र ने इस घटना की सूचना 20 अप्रैल 2025 को आदमपुर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से शिकायत कर अपनी रकम वापस कराने तथा उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम के निर्देश पर आदमपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यह फायदे का बजट है, रोजाना की चीज सस्ती हुई है। कैसर एवं शुगर की दवाइयां सस्ती हुई हैं। कुल मिलाकर यह जनमानस के लिए फायदे का बजट है। आम जनता वेतन भोगी एवं व्यापारियों को फायदा होगा। - मुकेश गुप्ता, प्रदेश महामंत्री, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट मील का पथर साबित होगा। स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को दी गई राहत से आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। यह बजट देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। - कुसुम लता गोयल, जिला महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा

एमएसएमई सेक्टर को दी गई राहत और प्रोत्साहन से छोटे उद्यमों को मजबूती मिलेगी। सरसे ऋण और नीतिगत सहयोग से स्थानीय उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने वाले प्रावधान युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करेंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। - वैभव अग्रवाल, प्रबंध निदेशक

बजट के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। यह बजट देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। छात्राओं के लिए छात्रावास की घोषणा सराहनीय है। - सारिका गुप्त, गृहणी

वर्ष 2027 में विकसित भारत के लक्ष्य को वृद्धिगत रखते हुए, तकनीकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर, महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए, गांव, गरीब, किसान के कल्याण वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। - सुरमित गुप्ता एडवोकेट, पूर्व महासचिव तहसील बार एसोसिएशन

बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई टोस गारंटी नहीं दी गई है, जिससे किसान वर्ग में असंतोष है। खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए बजट में टोस प्रावधान नहीं किए गए। साथ ही कृषि ऋण माफ़ी जैसे मुद्दे पर भी सरकार ने किसानों को टोस राहत नहीं दी। - चौधरी गुरमीत सिंह, किसान मंडी धनौरा

बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई टोस गारंटी नहीं दी गई है, जिससे किसान वर्ग में असंतोष है। खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए बजट में टोस प्रावधान नहीं किए गए। साथ ही कृषि ऋण माफ़ी जैसे मुद्दे पर भी सरकार ने किसानों को टोस राहत नहीं दी। - चौधरी गुरमीत सिंह, किसान मंडी धनौरा

बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई टोस गारंटी नहीं दी गई है, जिससे किसान वर्ग में असंतोष है। खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए बजट में टोस प्रावधान नहीं किए गए। साथ ही कृषि ऋण माफ़ी जैसे मुद्दे पर भी सरकार ने किसानों को टोस राहत नहीं दी। - चौधरी गुरमीत सिंह, किसान मंडी धनौरा

माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने किया गंगा में स्नान

संवाददाता, गजरौला

अमृत विचार: रविवार को माघ पूर्णिमा पर ब्रजघाट व तिगरी स्थित गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान आस्था की डुबकी लगाते हुए सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य दिया। स्नान के समय जयकारों से मां गंगा के स्नान घाट गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने ब्राह्मण व गरीब निराश्रितों को तिल, गुरु, कंबल व वस्त्र दान किए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। ब्रजघाट में माघ पूर्णिमा पर डुबकी लगाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व अमरोहा बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर समेत जनपदों से श्रद्धालुओं

के बाहर लगे टीन शैंड में गुजरानी पड़ी। देर रात को ही अधिकांश श्रद्धालु गंगा किनारे एकत्र हो गए थे। वहीं सैकड़ों धर्मशाला, आश्रम और मंदिर परिसर भीड़ से फुल होने पर हजारों की भीड़ को स्टेशन रोड, मैन बाजार, आरती स्थल समेत दुकानों

● बृजघाट व तिगरी में आसपास के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के भी श्रद्धालु जुटे

श्रीकृष्ण आश्रम, गंगा मंदिर समेत विभिन्न धर्मस्थलों में अपने ईष्ट देवों की पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की मनोती मांगी। उधर, तिगरी में भी पहुंचकर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं में ब्राह्मण, गरीब-निराश्रितों को भोजन-वस्त्र का दान देकर पुण्य कमाया। तिगरी के पंडित गंगासरन शर्मा ने कहा कि माघ माह में सूर्योदय से पूर्व गंगा में डुबकी लगाकर गरीब-निराश्रितों को भोजन-वस्त्र, लकड़ी, तिल का दान देने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है।

हसनपुर क्षेत्र के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि

हसनपुर, अमृत विचार: क्षेत्र में शनिवार आधी रात के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। गेहूं व सरसों की फसल को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। गंगेश्वरी क्षेत्र से गांव उकावली निवासी गंगासरन व नाजिम ने बताया कि शनिवार रात 2 बजे करीब 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। कंचे से बड़ा ओला गिरा। ओले सड़कों से लेकर लोगों की छत व घरों के आंगन तक जाम गए। हर ओर ओले की सफेद चादर सी दिखाई दे रही थी। लोगों ने आंगन व छतों से टब आदि में भरकर ओलों को हटाया। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि से क्षेत्र के 20 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं।

पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी को जान से मारने की धमकी

संवाददाता, हसनपुर

अमृत विचार: थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव निवासी एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। संभल के थाना क्षेत्र के गांव सिरसा की महेया निवासी पीड़िता रवि ने तहरीर दी कि उसकी शादी 18 वर्ष पूर्व सौंप के साथ हुई थी, जिससे उसके दो बेटे हैं। पति ने दूसरी शादी कर ली और अब मुरादाबाद में रह रहा है। विरोध करने पर पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि 31 जनवरी

की रात जब वह अपने मायके कोतवाली क्षेत्र के गांव सतेड़ा में थी, तब चार नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश की और शोर मचाने पर भाग निकले। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जाते-जाते उसे दोबारा हमला करने की धमकी दे गए हैं, जिससे उसका पूरा परिवार दहशत में है। वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया तहरीर प्राप्त हुई है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

हिंदू सम्मेलन में एकता का दिया संदेश

संवाददाता, हसनपुर

विभाजन में उलझा रहा। अब समय आ गया है कि समाज आत्ममंथन कर एकजुट होने का संकल्प ले। नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने डॉक्टर सुमेधा को मां दुर्गा की मूर्ति भेंट की। अध्यक्षता राकेश अग्रवाल ने की। समाजसेवी बहन सीता आर्य के द्वारा स्वागत किया गया। सह जिला कारवां नरेंद्र, संचालक दीपक कुमार, सोनू, रजनीकांत, विश्वनाथ, संजय सहदेव, अपर्णा गुप्ता, विजय, चंकी सहदेव, मुकेश गुप्ता, संजीव त्यागी, अंकित शर्मा, अक्षी अग्रवाल, आदेश अग्रवाल, विक्रम महंत, मधुर अग्रवाल, आदेश मित्तल, गणेशी राणा, टेकचंद चौहान, सीता आर्य, बबीता सैनी सहित काफी लोग मौजूद रहे।

रविदास जयंती पर निकली शोभा यात्रा

संवाददाता, हसनपुर

अमृत विचार: संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सम्मिलित झांकियां नगर वासियों का मन हो रही थी। शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु रविदास के 655 वें जन्मदिन शोभा यात्रा मोहल्ला कोट पश्चिम खेवान स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग पर भ्रमण करती हुई वापस शिव मंदिर पर पहुंच कर संपन्न हुई। आरंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने किया। शोभायात्रा में बाबा भीमवार नंदावेडकर, राम दरबार, गुरु रविदास, भारत माता, कबीर दास, मीरा कृष्ण,



शोभा यात्रा में सम्मिलित झांकी।

● अमृत विचार

गुरु गोरखनाथ सहित एक दर्जन झांकियां नगर वासियों का मन हो रही थी। अध्यक्षता फतेहचंद ने की एवं संचालन मनोज कुमार ने किया। पंडित धर्मवीर जाटव, फतेह सिंह चंद्र, मनोज कुमार, महेंद्र सिंह आर्य, सुशील भगत,

लता सागर, रामवीर सिंह, अंकुर सेठी, नवल जाटव, मालवा सिंह, पीतम सिंह, बबलू सिंह, आसाराम, विठू सागर, दिनेश कुमार, चंचल सागर, अजय सिंह, महिपाल सिंह, दीपक कुमर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

प्रदूषण के खिलाफ जारी है किसानों की हुंकार

संवाददाता, गजरौला

अमृत विचार: भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के प्रदाधिकारियों का प्रदूषण के खिलाफ रविवार को भी क्षेत्र के गांव शहबाजपुर डोर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। नरेश चौधरी ने कहा अन्नदाता का सहयोग करने के बजाय सरकार व प्रशासन किसानों का मखौल उड़ाने का काम करता है। गजरौला क्षेत्र के किसानों की आवाज

कोई सुनने वाला नहीं है। क्षेत्र में जहरीले पानी को लेकर बहुत बड़ी आपदा आई है। लेकिन अमरोहा का प्रशासन न तो अभी तक कोई जांच कर पाया और न ही लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टर भेजे गए। मंडल अध्यक्ष एहसान अली ने प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण चौहान, मंडल अध्यक्ष एहसान अली, होमपाल सिंह, विजय सिंह, चंद्रपाल सिंह, प्रकाश सिंह, सतिराम सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राम प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।

सूचना
सूचित किया जाता है कि मेरा मूल (आवंटन) प्रदेश पत्र, एवं मूल कब्जा प्रमाण पत्र, जो कि भवन संख्या- 201, (EWS), दुर्बल आय वर्ग, स्थित आवास विकास कालोनी योजना संख्या 3 सचिवल लाईस रामपुर में है व जिसका क्षेत्रफल 30.15 वर्ग मीटर है जो कि आवास विकास परिषद रामपुर द्वारा मूल आवंटन क्रेता शब्द पुत्र नवू निवासी- 201, आवास विकास कालोनी योजना संख्या 3. नूर महल. रामपुर को अर्बिटल व विक्रय किया गया था। दिनांक- 28.01.2026 को समय लगभग 2.00 बजे दिन खोद चौराहे के पास, फोटो स्टेट करने जाते समय थाना अजीम नगर क्षेत्र में, उक्त भवन संख्या 201 के उक्त दोनों पत्र मूल (आवंटन पत्र) प्रदेश पत्र व कब्जा प्रमाण पत्र कहीं मिस्लेस हो गये हैं जो कि काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिल सके हैं। उक्त कागजात को गुमशुदगी की सूचना थाना अजीम नगर, रामपुर पर जी.डी. संख्या 49 पर दिनांक 29.01.2026 को अर्बिटल का चुकी है। उक्त दस्तावेजों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग गलत व गैर कानूनी होगा। उक्त संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक शाखा काशीपुर आंगा, रामपुर में बंधक की जा रही है। यदि किसी को इस संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो उसकी सूचना 15 दिन में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा काशीपुर आंगा, रामपुर के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि बीत जाने पर उक्त संपत्ति पर कोई दावा अथवा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति अली पुत्र श्री तुफेल अहमद निवासी ग्राम खोद तहसील सदर, जिला रामपुर (उ.प्र.) मो.न. 9837705335

न्यूज ब्रीफ

अदिति गुप्ता ने शिक्षा जगत में बनाई मिसाल



जिलाधिकारी को पुस्तक भेंट करती अदिति।

चंदौसी, अमृत विचार : चंदौसी की अदिति गुप्ता शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं। 'बंगलुरु में अदिति पिछले 11 वर्षों से विद्याथियों के बौद्धिक, मानसिक और नैतिक विकास में सक्रिय हैं। वे द ग्रीन स्कूल, बंगलुरु में हिंदी विभाग की सीनियर कक्षाओं की विभागाध्यक्ष हैं और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड की लेखिका भी हैं। उनकी पुस्तक 'शब्दों से विचारों तक' विद्याथियों को निबंध लेखन, सोचने और जीवन समझने की प्रेरणा देती है। पुस्तक की एक प्रति अदिति ने जिलाधिकारी संभल डॉ. राजेन्द्र पैंसिया को भेंट की।

सड़क निर्माण के चलते

26 तक रुट डायवर्जन

बबराला, अमृत विचार : नगर पंचायत द्वारा मुख्य बाजार में बड़ी पुलिस से अनूपशहर रेलवे फाटक तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 126 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। नगर पंचायत चेयरमैन हर्षवर्धन वाघोण्ये ने कहा कि निर्माण अवधि के दौरान वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। डायवर्जन के अनुसार, नगर से मुख्य बाजार होकर बुलंदशहर, गाजियाबाद व दिल्ली जाने वाले वाहन यारा फर्टिलाइजर्स रेलवे फाटक से रजपुरा-केसरपुर तिराहा होते हुए अनूपशहर की ओर जा सकेंगे। वहीं बदायूं की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहन गुन्नौर, नरोरा, डिबाई व बुलंदशहर मार्ग का उपयोग करेंगे। नगर पंचायत प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि अशुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।

मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत

बबराला, अमृत विचार : जुनावई थाना क्षेत्र में मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर देर रात पहल धर लीट रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के सैमला करनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय इंदुपाल पुत्र रामपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रधान की सास के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा

पहलवाड़ा गांव में चुनावी रंजिश में गोली मार कर दी थी ग्राम प्रधान की सास की हत्या

● सपा विधायक रामखिलाड़ी यादव मौके पर पहुंचे, अफसरों से की बात

कार्यालय संवाददाता, संभल/बबराला

अमृत विचार: थाना बबराला क्षेत्र अंतर्गत पहलवाड़ा गांव में शुक्रवार रात प्रधानी चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग में मारी गई ग्राम प्रधान की सास के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने हंगामा किया। सपा विधायक के समझाने और अफसरों के आश्वासन के बाद परिजन माने। कड़े पुलिस प्रबंध के बीच राजघाट गंगा तट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया।

शुक्रवार रात गांव पहलवाड़ा में प्रधानी चुनाव को लेकर मौजूदा प्रधान मीरा देवी के पति और इनके बार प्रधानी के दावेदार पवन और प्रधान प्रत्याशी सुभाष पुत्र रामबाबू पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई थी। इस दौरान ग्राम प्रधान मीरा देवी की सास प्रेमवती के सीने में गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। दूसरे पक्ष का देवेश घायल हुआ। गोली उसका कान चीरते हुए निकल गई। शनिवार को प्रेमवती के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनो को सौंप दिया गया। रविवार सुबह तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनो ने शव रखकर हंगामा और नारेबाजी कर हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। गुन्नौर से सपा विधायक रामखिलाड़ी यादव अपने पुत्र अखिलेश यादव के साथ पहुंचे। उन्होंने पुलिस और उच्च अधिकारियों से बातचीत



हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुटे ग्रामीण व परिजन।

● अमृत विचार

की। अफसरों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक के समझाने के बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए राजघाट ले जाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि किसी तरह का जाम नहीं लगाया गया है। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तभी सामान लेने व पिंडदान के लिए बबराला में रुके थे।

बहरहाल पुलिस ने पवन की तहरीर पर नीतीश कुमार, सुभाष पुत्र

रामबाबू, मनीष, वीरेश पुत्र राजवीर सिंह, रामबाबू पुत्र मुकुट सिंह, वीरपाल, बलराम पुत्र आसाराम, लाखी पुत्र बलराम, गिरीश पुत्र जुगेन्द्र, राजवीर, सत्यपाल पुत्र मलखान, नीरज पुत्र वीरपाल तथा 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी सौरभ त्यागी ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

बरेली-बांदीकुई पैसेंजर के पुनः संचालन पर जताई खुशी



चंदौसी में ट्रेन संचालन की खुशी मनाते व्यापारी।

● अमृत विचार

संवाददाता, चंदौसी

अमृत विचार: बरेली-बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन के पुनः संचालन से यात्रियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इस रूट पर कोई ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रविवार को अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल की युवा इकाई

ने रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। नगर अध्यक्ष अनुज वाघोण्ये ने कहा कि इससे मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन बरेली से बांदीकुई नियमित रूप से चलेगी। सभासद अमन कोरी, ऋषभ रस्तोगी, निशांत शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।

बहन की विदाई के बाद भाई ने दी जान

संभल, अमृत विचार: बहन की विदाई के बाद छोटे भाई ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

थाना रायसती क्षेत्र के मोहल्ला जगत निवासी मुकीम खान की बेटी शाजिया का रविवार को निकाह था। बहन की विदाई के बाद मुकीम खान का 16 वर्षीय पुत्र अपनी मां शकीला से चाबी लेकर घर पहुंचा। वहां फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चार घंटे तक परिवार ने छिपाए रखा। इसी दौरान कुछ लोगों ने पंजु सराय पुलिस चौकी में सूचना दी। थाना प्रभारी निशांत कुमार राठी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि किशोर को दफन करने की तैयारी चल रही थी। थाना प्रभारी ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए।

चुनौतियों से निपटने को हिंदू समाज रहे एकजुट

● संघ के शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन

कार्यालय संवाददाता, संभल/सिरसी

अमृत विचार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर जनपद संभल के सिरसी व सरायतरीन में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सरायतरीन में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदू समाज को अपनी संस्कृति से जुड़ने और बिखरे हुए समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। सिरसी में भी छुआछूत को मिटाने व एकजुट रहने की बात कही गई।

रविवार को सरायतरीन एवं लाडम सराय बस्ती की ओर से सरायतरीन के बीडी इंटर कॉलेज परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन में

कॉन्फ्रेंस व दस्तारबंदी में इल्म और अमन का दिया संदेश

संभल, अमृत विचार: सरायतरीन स्थित मदरसा फ़ैज़ उल उलूम में वार्षिक जलसा तहफ़फुज-ए-इस्लाम कॉन्फ्रेंस एवं दस्तारबंदी की शुरुआत तिलावत-ए-कुरान से हुई। मशहूर मुफ्ती मोहम्मद आकिल मिस्वाही ने कहा कि कुरान में कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सच्चा इल्म वही है, जो ईंसान को अपने रब की पहचान कराए और समाज में समानता व भाईचारे का संदेश दे। मौलाना तौसीफ़ मिस्वाही ने कहा कि मदरसा शिक्षा न केवल दीन की हिफाजत करती है, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलसे का मुख्य आकर्षण उन छात्रों की दस्तारबंदी रही, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। मदरसा प्रबंधक शलीम अशरफ सलामी, हाजी नूर इलाही, मौलाना कामिल मिस्वाही, मौलाना अब्बास अजमली, मौलाना अजीमुर रहमान, मौलाना फ़हीम, मौलाना आरिफ़ मूसापुरी, कारी अकबर, मौलाना आदिल मिस्वाही, मौलाना शोकेत, मौलाना आलिम, कारी इश्तियाक, हाजी ताहिर सलामी, शराफ़त हुसैन आदि मौजूद रहे।

माघ पूर्णिमा पर उमड़ श्रद्धालुओं का सैलाब



राजघाट गंगा तट पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर जुटे श्रद्धालु।

● अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, संभल/बबराला

● हजारों श्रद्धालुओं ने किया राजघाट गंगा में स्नान

अमृत विचार: माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजघाट गंगा तट सहित अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बरसात व सर्दी के बावजूद गंगा में डुबकी लगाकर विधि विधान से गंगा पूजन किया। गंगा घाट व मार्गों पर पुलिस के पुख्ता प्रबंध किये गये थे। राजघाट गंगा तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ नजर आई। गंगा स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य एवं मंगल कामना की। घाट पर हर-हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कई श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर दीपदान कर मां गंगा से मनोकामनाएं भी कीं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा में स्नान के दौरान

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की तैनाती की गई थी। पुलिस कर्मी लगातार घाट पर गश्त करते रहे और भीड़ को नियंत्रित करते नजर आए। नगर पंचायत बबराला की ओर से गंगा घाट पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई। नगर पंचायत कर्मियों द्वारा दिनभर साफ-सफाई का कार्य किया गया। घाट परिसर में लगे मेले में भी रौनक देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ मेले का आनंद लिया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजघाट के साथ ही अनूपशहर जेपी घाट, सिसौना डांडा, साधुमणि गंगा घाट, हरिबाबा बांध गंगा घाट पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भूत संगम देखने को मिला।

हर परिवार के विकास पर सरकार कर रही काम

कार्यालय संवाददाता, संभल/बबराला

अमृत विचार: तीन माह चलने वाले राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान 2.0 का विकासखंड गुन्नौर में शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार होममाइंड्स एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हर जनपद और हर गांव ही नदी बल्कि हर परिवार के विकास के लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव, पूर्व मंत्री व भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू उपस्थित रहे। अतिथियों ने आईसीडीएस, बेसिक शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जल संरक्षण,



संबोधित करते जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति व अन्य।

पॉलिथीन के प्रयोग को कम करने और कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने संपूर्णता अभियान 2.0 के उद्देश्यों, नए लक्ष्य, निरंतरता, संस्थागतकरण, अभिवरण और जनभागीदारी पर प्रकाश डाला। बताया कि यह अभियान देश के 112 जिलों एवं 513 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है।

● गुन्नौर में संपूर्णता अभियान 2.0 आरंभ, प्रभारी मंत्री ने दिया जनभागीदारी का संदेश

विद्यालयों में बालिका शौचालय के बारे में बताया। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि गत वर्ष छह में से पांच संकेतांकों में संतुष्टि प्राप्त करने पर जनपद को रजत पदक मिला था। इस वर्ष सभी संकेतांकों को संतुष्ट करना प्राथमिकता रहेगी। पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। सीएमओ डॉ. तरुण पाठक, प्रभागीय वनाधिकारी प्रीति यादव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख गुन्नौर हनी यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिंदू सम्मेलन में समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर जोर

चंदौसी, अमृत विचार: संभल गेट क्षेत्र में रविवार को आयोजित हिंदू सम्मेलन में समाज, संस्कृति, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य वक्ता मनीष सिंह ने कहा कि हिंदुओं को संगठित होकर राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने संघ की स्थापना और स्वयंसेवकों द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं समाज सेवा में योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि वंदे मातरम् को 150 वर्ष हो चुके हैं और राष्ट्रगीत से आपत्ति रखने वालों को देश में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। डॉ. संदीप वेदालंकार, संतोष जैन, आचार्य ऋष्यपर्ण व प्रभु, मुदित गर्ग, शुभम अग्रवाल, ओमवीर, अनिल, विवेक सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे।

सनातन संस्कृति विश्व को दिशा देने वाली एकजुट रहें हिंदू

चंदौसी, अमृत विचार: आवास विकास स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर पार्क में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर हरिकान्त महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति विश्व को दिशा देने वाली है। हिंदू समाज को जातियों में बंटने की निर्माण को लेकर आचार्य धर्म की रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए अपने तन, मन और धन को समर्पित करना आवश्यक है। सोमानंद सरस्वती महाराज ने राष्ट्र सेवा को आधुनिक अर्थव्यवस्था यज्ञ बताया। विभाग संयोजक कुटुंब प्रबोधन महावीर, समिति के अध्यक्ष राकेश पाठक, हिमांशु अग्रवाल, डॉ. दुर्गा टंडन, राजीव गुप्ता, सुरेश सैनी, अजय जैन, पवन अग्रवाल, नीलम राय, आकृति गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

छोटे किसानों की उपेक्षा चिंता का विषय: मोहिनी मोहन

संवाददाता, संभल

अमृत विचार: भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि बजट में कुछ सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन छोटे किसानों से जुड़ी कई समस्याओं को अनदेखी की गई है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि बजट में 500 अमृत सरोवरों का निर्माण, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पालन को सुदृढ़ करना तथा पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने जैसे कदम सराहनीय हैं। इसी प्रकार फसल विविधीकरण योजना के तहत उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देना, जिसमें नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को शामिल किया गया है, एक सकारात्मक पहल है। ग्रामीण महिला समूहों

बजट में गरीब-मध्यम वर्ग की अनदेखी

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए निराशाजनक है और गरीब व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला साबित होगा। बजट किसानों और गरीब मजदूर वर्ग को राहत देने के बजाय उन्हें और कठिन परिस्थितियों में धकेलने वाला है।

को सशक्त बनाने के लिए ई-मार्ट की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है। बजट में छोटे किसानों की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की ऊंची दरें किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना में किसी प्रकार की बढ़ोतरी या मजबूती नहीं की गई।

सिटी डायरी



संत शिरोमणि रविदास जयंती पर निकाली शोभायात्रा

संभल, अमृत विचार : संभल तहसील क्षेत्र के लखौरी जलपुर में रविवार को संत शिरोमणि रविदास जयंती श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक समरसता के वातावरण में धूमधाम से मनाई गई। राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती और संत शिरोमणि रविदास की झांकियों विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभायात्रा अखंडकर धर्मशाळा से डाकखाना चौराहा, होली चौक से गुजरी। थाना नखासा प्रभारी संजीव कुमार बालिदान पुलिस फोर्स के साथ शोभायात्रा में मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजक किशनपाल ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। गोपाल सिंह, जय सिंह, मनोहर, चंद्रपाल सिंह, समय सिंह, मदनपाल, रामकिशोर, मुकेश फौजी, बृजपाल सिंह, प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, सोनू, कलुआ सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।



माघ पूर्णिमा पर प्रभात फेरी का समापन, जुटे श्रद्धालु

बबराला, अमृत विचार : बाधक में माघ मास के दौरान प्रतिदिन निकाली जा रही प्रभात फेरी का सोमवार को समापन हो गया। श्रद्धालु राजघाट पहुंचे, जहां गंगा स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान किए। स्नान के उपरांत प्रभात फेरी पुनः गांव में भ्रमण करती हुई नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। समापन अवसर पर हवन-पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आहुतियां दीं। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संत रविदास जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान शशीराम सिंह यादव सहित भुवनेश शर्मा, प्रभाकर कुशवाहा, बंटी पाल, मोहित सक्सेना, रूप किशोर शर्मा, राजपाल, उमेश शर्मा, राधेश्याम कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, विनोद सागर, वीरपाल कुशवाहा, विशाल सागर, प्रेमपाल कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।



पुलिस चौकी के मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा

संभल, मनोटा, अमृत विचार : ऐरोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर पुलिस चौकी परिसर में नवनिर्मित श्री बालाजी हनुमान मंदिर में रविवार को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आचार्य धर्मेश शर्मा एवं विधिन पाराशर ने पूजा-अर्चना कराई। अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां देकर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और देश कल्याण की कामना की। चौकी प्रभारी उपेंद्र मलिक ने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। रजमान के रूप में थाना अध्यक्ष लवनेश चौधरी, देवेश चौधरी, रजनी देवी, उपेंद्र मलिक, अनु मलिक, रवि प्रधान, निशु देवी, नकुल जिला पंचायत सदस्य, गुरमीत ओलख, सहदेव, कुशल कुमार, रोहित, मोहित, विपिन चौधरी, अनुज कुमार, चमन प्रधान चमन सिंह, आम कुमार, शाहिद सहित संकेडों क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।



श्रद्धापूर्वक मनाई गई संत रविदास की जयंती

चंदौसी, अमृत विचार : महापुरुष स्मारक समिति एवं सर्वसमाज जागरूकता अभियान भारत के संयुक्त तत्वावधान में संत शिरोमणि रविदास की जयंती श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ब्रह्मण्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि माधव मिश्र ने कहा कि संत रविदास दयालु, दानवीर और मानवतावादी विचारों के महान संत थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। डॉ. महेश कुमार गुप्ता, डॉ. अरविंद कुमार गुप्ता, सुरेशचंद्र शर्मा, डॉ. निशा गुप्ता, डॉ. नितिन कौशिक, अंकित वाण्यी, पंकज वाण्यी, अनमोल मिश्रा, हिमांशु यादव, विकास यादव, शिवकुमार, अफजल खान, शोभा यादव, सरोज कुमारी, सपना, अश्विनी, रितु कुमारी, कासिम, केशव यादव आदि मौजूद रहे।

न्यूज़ ब्रीफ

जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा के साथ 10 लोग गिरफ्तार

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से 25 लाख 18 हजार 5 सौ की जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की गयी है। इस मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के रक्सौल में जाली मुद्रा के बड़े कारोबारियों नेटवर्क का खुलासा किया है। सीमावर्ती क्षेत्र हरेया थाना की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने बड़ी कर्वाई करते हुए 25 लाख की जाली नेपाली मुद्रा और 18,500 की जाली भारतीय मुद्रा के साथ 4 नेपाली नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गांजा तस्करो के हमले में आबकारी कांस्टेबल की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हाल में कथित रूप से गांजा तस्करो के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 23 वर्षीय महिला आबकारी कांस्टेबल की यहां सरकारी निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी सीया को 23 जनवरी को गांजा तस्करो ने उस वक्त कार से टक्कर मार दी थी जब सीमा के नकार को रुकने का इशारा किया था। टक्कर मारे जाने से सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सीमा को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें 'निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (निम्स) में स्थानांतरित कर दिया गया जहां शनिवार रात को उन्होंने दम तोड़ दिया।

रांची में अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर छह बसें जलकर राख

रांची। रविवार दोपहर रांची के एक अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर लग्नी भीषण आग में वहां खड़ी कम से कम छह बसें जलकर नष्ट हो गईं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खादगढ़ में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग एक खराब बस में लगी और उसने जल्द बस के अगल बगल खड़ी अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। खादगढ़ पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि आग लगने के समय किसी भी वाहन में कोई भी मौजूद नहीं था।

राकांपा राजग में बनी रहेगी, विलय की अटकलों पर बोले सुनील तटकरे

कहा-संगठन दिवंगत अजित पवार की विचारधारा और मार्ग पर आगे बढ़ेगा

मुंबई, एजेंसी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा नीत राजग का हिस्सा बनी रहेगी और संगठन दिवंगत अजित पवार द्वारा निर्धारित विचारधारा एवं मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यह दावा किया जा रहा था कि राकांपा और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विलय की घोषणा की तारीख 12 फरवरी तय कर दी गई थी। राकांपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तटकरे ने कहा कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा रुख स्पष्ट है। हम पार्टी

और अजित दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस रुख पर अडिग हैं। रायगड के सांसद ने कहा कि हम राजग के साथ हैं और राजग के साथ ही रहेंगे। अजित दादा ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया था। तटकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ तालमेल का निर्णय अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की जल्दबाजी पर आलोचना का जिक्र करते हुए

मैं राकांपा अध्यक्ष नहीं, खबरें निराधार : पटेल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी। पटेल ने एक्स पर कहा कि मैंने राकांपा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के संबंध में मीडिया में प्रसारित हो रही कुछ खबरों पर गौर किया है। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल का यह बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतना बड़ा फैसला हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और विधायकों से परामर्श करने, हमारे सर्मापित पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने और हमारे सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं और सामूहिक इच्छा का सम्मान करने के बाद ही लिया जाएगा।

तटकरे ने कहा कि संविधान सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय महाराष्ट्र के हित में और राकांपा को मजबूत करने के लिए

लिया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिरता और अजित पवार के विकसित राज्य के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए उनके शपथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है।

फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर गोलीबारी

मुंबई, एजेंसी

मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर शनिवार देर रात हुई गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी के समय शेट्टी अपने घर पर थे या नहीं। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने रात करीब पौने एक बजे नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की।

पांच गोलियां चलाई, पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

चलाई। क्षेत्रीय पुलिस और अपराध शाखा की टीम मामले की जांच कर रही है। अधिकारी ने कहा कि चारजे मालवाड़ी थाने के कर्मियों द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान पुणे शहर के कारवेगनर और धायरी इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि जुहू पुलिस और अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंचीं तथा जांच शुरू कर दी। घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस इमारत के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल कर रही है। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान और बैलिटिस्टक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची। निर्माता एवं निर्देशक शेट्टी गोलमाल, सिंघम और चैंडई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

पलामू में पति-पत्नी और बेटे की हत्या बहु-पोती गंभीर

रांची, एजेंसी

झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसडी गांव में पति-पत्नी और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान विजय भुइयां, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। इस हमले में विजय भुइयां की बहु नीलू देवी और पोती ममता कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को तीन लोगों की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

विदेश मंत्रालय ने कहा-ध्यान भटकाने का काम कर रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हुई हिंसा में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें 'निराधार' बताया और कहा कि ऐसा कहकर पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को 'बेतुके दावे' करने की बजाय अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

सिरे से खारिज करते हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की उसकी सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हर बार जब कोई हिंसक घटना होती है, तो ऐसे दावों को दोहराने की बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों की लंबे समय से चली आ

गुरु रविदास के नाम का हुआ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम

जालंधर, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का आंनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लानों भी गए। इस बीच, मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे पंजाब में बुनियादी विमानन ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। रायकोट में उपखंड के हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क

- प्रधानमंत्री ने हलवारा हवाई अड्डे पर किया टर्मिनल का उद्घाटन
- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

में उल्लेखनीय सुधार होने और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन परियोजना को पंजाब सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 54.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के जालंधर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

बलूचिस्तान में हुई हिंसा में भारत का हाथ नहीं पाकिस्तान के आरोप को निराधार बताया

बलूचिस्तान में 16 जगहों पर हुए हमले

गौतलब है कि शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 16 जगहों पर हमले हुए। क्वेटा, चादर, कल्लात, खारान, मस्तुंग, पसनी, दलबंदिन, नोशकी, बुलाइटा, टंप, मच और आसपास के इलाकों में विस्फोट और सशस्त्र हमलों की सूचना मिली। बलूचिस्तान में हुई हिंसा की जिम्मेदारी शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 'ऑपरेशन हेरोफ फेज दो' के हिस्से के रूप में ली। बीएलए के अनुसार दस घंटे की अवधि में 14 शहरों में हुए हमलों में सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

हमलों में मारे गए थे 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी

बलूच समूह ने दावा किया कि हिंसा में 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, 18 को जंदा फकाड़ा गया, 30 सरकारी संघर्षियों को नष्ट कर दिया गया या जकट कर लिया गया और 23 दुश्मन वाहनों में आग लगा दी गई। बीएलए ने यह भी कहा कि उसने केंद्रीय सैन्य मुख्यालय सहित कई दुश्मन चौकियों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे कई शहरों में आवाजही प्रतिबंधित हो गई। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में हमलों की पुष्टि हुई।

रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है। यह बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा हमलों

में भारत पर शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। भारत ने पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे दमन को उजागर करके पलटवार किया।

बजट पर प्रतिक्रियाएं

एमएसएमई और मैनुफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्रीय बजट 2026-27

- आईआईए लखनऊ में बजट देखने और चर्चा सत्र का हुआ आयोजन
- उद्योग जगत ने बताया भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित बजट



कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने रविवार को आईआईए भवन, लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर चर्चा सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नीति विशेषज्ञ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर पर आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमित कुमार सिंह, डिविजनल

आई-टेक टूल रूम और जलमार्गों पर फोकस का स्वागत
आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने कहा कि आई-प्रेसिजन कंपोनेंट्स के लिए आई-टेक टूल रूम की स्थापना, चैंपियन एमएसएमईज का निर्माण और रेयर अर्थ मैनेट पर नए सिरे से फोकस, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग में धरेलू क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 22 नए जलमार्गों और कटेनर मैनुफैक्चरिंग सुविधाओं की घोषणा को दूरदर्शी कदम बताया।

एमएसएमई के लिए तत्काल उपायों की कमी
आईआईए के पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए अपेक्षित स्तर का तात्कालिक समर्थन नहीं दिखता। कई घोषणाएं लंबी अवधि की हैं, जबकि वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए एक-वर्षीय तत्काल उपायों की जरूरत थी।

जम-ट्रेड्स इंडीग्रेसन से सुधरेगी एमएसएमईज की लिक्विडिटी
आईआईए की बैंकिंग समिति के चेयरमैन केके अग्रवाल ने जम को ट्रेड से जोड़ने की घोषणा को अहम सुधार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमईज की लिक्विडिटी समस्याएं कम होंगी, अधिक सरकारी संस्थान और पीएसयू ट्रेड्स के दायरे में आएं और पेमेंट साइकिल तेज होगी।

एफटीए अनुरुप कस्टम इयूटी स्ट्रक्चर से स्वदेशीकरण को बढ़ावा
आईआईए की जीएसटी समिति के चेयरमैन कपिल वैश्य ने कहा कि तैयार माल के बजाय कंपोनेंट्स पर कस्टम इयूटी-कम करना, हाल ही में घोषित ईयू-एफटीए के अनुरुप है। यह

नीति लंबे समय में स्वदेशीकरण को मजबूत करेगी और धरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाएगी।

चैंपियन एमएसएमईज और इंडस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा पर जोर
आईआईए के चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां, फाइनेंस और टेक्सेशन शाशांक शेखर गुप्ता ने कहा कि बजट में इंडस्ट्रियल ग्रीथ और मैनुफैक्चरिंग पर दिया गया है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने की सरकार की यह मंशा को स्पष्ट करता है। इससे धरेलू मैनुफैक्चरिंग और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को बल मिलेगा।

कैश फ्लो को मिलेगी मदद
सीए अशोक सेठ ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस में कमी से कारोबारियों के हाथों में अधिक नकदी आएगी, जिससे कैश फ्लो मैनेजमेंट और व्यवसाय विस्तार में मदद मिलेगी।

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार: केंद्र सरकार के आम बजट में एक ओर आयकर स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, वहीं सराफा कारोबार को भी कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। सोना-चांदी पर कस्टम इयूटी में कटौती न होने से बाजार में मायूसी छाई रही और बजट के बाद सराफा के रेटों में तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक और औद्योगिक सामान सस्ते होने से सीमित वर्ग को राहत जरूर मिली है।

रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर सुबह से ही व्यापारी, उद्योगपति, आमजन, युवा वर्ग समेत अन्य लोग टीवी मोबाइल पर बजट का प्रसारण देखते रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री जब

सराफा में कम नहीं हुई कस्टम इयूटी

तक भाषण करती रही। तब तक लोग अपने आंकड़े लगाने में जुटे रहे। उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में उन्हें छूट दी जाएगी। इसलिए व्यापारी और टैक्सपेयर निगाहें बांधे रहे। मगर एक बजे के बाद बजट की तरकीर पूरी तरह साफ हो गई। बजट में आयकर की नई कर व्यवस्था के तहत पहले से लागू टैक्स स्लैब को यथावत रखा गया है।

शून्य से तीन लाख रुपये तक आय पर टैक्स नहीं, तीन से छह लाख पर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख पर 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान पहले जैसा ही है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होने से करदाताओं को कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिल सकी। जिससे नौकरिपेशा लोगों को भी निराशा हाथ लगी। इतना ही नहीं बजट में सराफा कारोबारियों की उम्मीद पर भी पानी फिर गया।

गर्ल्स छात्रावास और महिला रोजगार बढ़ाने का स्वागत

कार्यालय संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: आम बजट में केंद्र सरकार ने गर्ल्स एजुकेशन और महिला रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। महिलाओं ने इसका स्वागत किया है। इससे जिले की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही प्रावधानों के मुताबिक इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर हर जिले में एक हॉस्टल बनाने का एलान किया

केंद्रीय आम बजट

बजट सुधारों को अपनाया गया है

केंद्र सरकार का युवा शक्ति ड्राइवर बजट है जो कि गरीबों, वंचित और पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित बजट है। चैंपियन एमएसएमई की कल्पना करते हुए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके अंतर्गत इक्विटी समर्थन जिसमें 10 करोड़ रुपये का फंड, व्यावसायिक सहायता एवं ट्रेड्स के माध्यम से तरलता सहायता के प्रावधान के साथ विनिर्माण क्षेत्र को अग्रिम क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर 2.0, टेक्सटाइल प्रमोशन, इलेक्ट्रॉनिक घटक योजना, किरायाती रेल सामग्री योजना एवं उच्च मूल्य और तकनीकी रूप में उन्नत हुए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जाना प्रशंसनीय है। यह बजट सरकार का कम कारोबारियों घाटे हेतु एक संतुलित बजट है।

-डॉ. राहुल कुमार मिश्रा, अर्थशास्त्र विभाग, खाजा मोड़नुईन चिरती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

'रेवडी संस्कृति' की जगह तकनीकी सशक्तीकरण पर दिया गया जोर

महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये तक के उद्यमिता ऋण और हर जिले में 'गर्ल्स हॉस्टल' के साथ-साथ, दिव्यांगजनों के लिए 'सहारा योजना' और 'दिव्यांगजन कौशल योजना' की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 'मैटल हेल्थ केयर' केंद्रों के विस्तार और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बुनियादी ढांचे में 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक निवेश, सात नए आई-स्पीड रेल कॉरिडोर और रक्षा क्षेत्र में 'ड्रोन शक्ति 2.0' भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़े कदम हैं। शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के 'बोलबाले' का साक्षी है। यह बजट 'रेवडी संस्कृति' के स्थान पर तकनीकी सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। -प्रो. अनामिका चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, -डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वासि विश्वविद्यालय, लखनऊ

पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार केंद्रित बजट

बजट में व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के रूप में स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और मध्यम मुद्रास्फीति को शामिल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन, हरित ऊर्जा, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष कर संरचना के सरलीकरण और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे जैव-फार्मा, मत्स्य पालन और अन्य अणुव्यापारिक कृषि क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों पर दीर्घकाल से रोजगार सृजन और आय वृद्धि के दृष्टिकोण में विशेष बल दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में उच्च और सतत विकास के लिए नए उपक्रमों तथा उपयुक्त बजट आवंटन की घोषणा की गई है, जैसे दुर्लभ खनिज खनन पर अनुसंधान, सेमीकंडक्टर मिशन, सर्मापित रासायनिक पार्क, वर्कों के लिए एकीकृत कार्यक्रम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रीथ फंड दिया गया है। परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया है। -प्रो. रमनात नायक, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहब आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

बजट में किसान, मजदूर, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इतना दूरगामी बजट से आम आदमी को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। सरकार वर्ष 2047 के सप्ताह यधि 2026-27 पर फोकस करते हुए बजट पेश करती तब लोगों का भला हो सकता था। - अजय सागर, जिलाध्यक्ष सपा-रामपुर

केंद्र सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे समान है, युवाओं, किसानों और सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। आम जनता को राहत देने वाला बजट होना चाहिए था। -मोहिबुल्लाह नदवी, सांसद रामपुर



गुप्ता, अचिरल कुमार, अक्षय कुमार सहित अनेक पदाधिकारी/उद्योगपति मौजूद रहे।



जेफरी एपस्टीन फाइल : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू से पूछताछ का बढ़ा दबाव

लंदन, एजेसी

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के अपराधों के स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। विंडसर की शाही स्थिति उनके भाई और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने रह कर दी थी।

मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। महिला का दावा है कि वह विंडसर कैसल एस्टेट स्थित एंड्रयू

● पूर्व प्रिंस पर महिला ने लगाया है यौन संबंध बनाने का आरोप

के शाही निवास में गई थी। ब्रिटिश राजपरिवार के पूर्व सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाली यह दूसरी महिला है। एंड्रयू लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, नवीनतम मामले में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जापान की यात्रा पर गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने हमेशा एपस्टीन के कृत्यों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता देते हुए मामले पर विचार किया है।

एपस्टीन के पत्राचार में मैक्रों का भी जिक्र

वाशिंगटन। जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर अपने पत्राचार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र किया था, जो एक प्रगतिशील एजेंडा को बढ़ावा देने की संभावनाओं में रुचि रखते थे। नए दस्तावेजों में रविवार को यह दावा किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एपस्टीन मामले में एक ई-मेल की कॉपी में यह कहा गया है। यह पत्र सितंबर 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बर्गेट ब्रेडे को एक ऐसी ई-मेल से भेजा गया था।

चिकित्सकों ने तलाश ली घातक सल्फास विषाक्तता की काट

● चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता

चंडीगढ़, एजेसी



केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किये गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में इंद्रावेनस

लिपिड इमल्शन प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है। बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका यूरोपियन रिच्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है। पीजीआईएमईआर के मुताबिक अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज

में अहम बदलाव आ सकता है। इसमें कहा गया कि अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

कम लागत में अब आसानी से मिलेगा उपचार

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि इंद्रावेनस लिपिड इमल्शन सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अवसर सीमित होती है। संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।

गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए था चुनौती

इसमें कहा गया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फोस विषाक्तता के उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

वर्ल्ड वीफ

सिंगापुर में हिंदुओं ने मनाया थार्डपुसम

सिंगापुर। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। मंत्री ने रविवार को थार्डपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से श्री शंदायतुपानी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3.2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ पालकुडम (दूध के पात्र) लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड (एचईबी) ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। शोभायात्रा में सिंगापुर के संस्कृति, समाज और युवा एवं श्रमशक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रथीणा वेलाइथन भी शामिल थीं।

आइवरी कोस्ट में हादसे में 14 की मौत

अबिजान। आइवरी कोस्ट में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हादसा सुबह करीब पांच बजे कबाडूगु इलाके में हुआ और इसमें एक ट्रक शामिल था जो अनाज ले जा रहा था और जिसमें अवैध रूप से 69 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री अमादो कोन ने कबाडूगु क्षेत्रीय परिषद प्राधिकरण के अधिकारियों को हादसे की शुरुआत जानकारी इच्छा करने के लिए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया है।

अमेरिका में गोलीबारी में पांच लोग घायल

न्यूयॉर्क। अमेरिका में लुइसियाना राज्य के विल्टन में शनिवार को "मार्डी ग्रास इन द केंद्री परेड के दौरान हुई गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना विल्टन में पूर्वी फेलिसियाना पैरिश कोर्टहाउस के बाहर हुई। पूर्वी फेलिसियाना पैरिश के शेरिफ जेफ टैविस ने स्थानीय समाचार आउटलेट डेब्ल्यूएफबी को बताया कि घायलों में एक छठ साल का बच्चा भी शामिल है। टैविस ने कहा कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस गोलीबारी के संबंध में एक गाड़ी की तलाश कर रही है।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को शुरू हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 500 सदस्य चुनेंगे।

अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आएगा

ट्रंप की जंग की धमकी पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दी चेतावनी

● खामेनेई ने दोहराया, ईरान पर हमलावरों को देंगे कड़ा जवाब

दुबई, एजेसी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य तकात का उपयोग करेंगे या नहीं।

उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल करते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तत्खापलट जैसा बताया और कहा कि इससे



ईयू सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यतः प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दे सकता

है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होमुंज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होमुंज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की दुलाई होती है। खामेनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना

हालिया प्रदर्शन तत्खापलट जैसा

दुबई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक तत्खापलट से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ईरान में 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरानी मुद्रा रियाल के पतन के विरोध में हुए थे। जल्द ही ये खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गया है।

फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम से पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येरवल्ली स्थित अपने फार्म हाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी बीआरएस अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनीतिक उपीड़न के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

सरकारों के हाथ से निजी कंपनियों को जा रही सत्ता

● संरा महासचिव ने किया शांति, न्याय, सतत विकास का आह्वान

न्यूयॉर्क, एजेसी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच शांति, न्याय और सतत विकास के लिए नए प्रयासों का आह्वान किया है। गुटेरेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया शायद हमारे समय के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण से गुजर रही है। सत्ता सरकारों से निजी तकनीकी कंपनियों के हाथों में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यवहार, चुनाव, बाजार और यहां तक कि संघर्षों को आकार देने वाली तकनीकों के बिना किसी सुरक्षा घेरे के काम करती हैं, तो प्रतिक्रिया नवाचार नहीं, अस्थिरता होती है।

महासचिव ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानि 2026 की प्रार्थमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2026 'अभी से निरंतर आश्चर्य और उथल-पुथल वाले वर्ष के रूप में आकार ले रहा है।' उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव के समय में वह उन सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, जो बताते हैं कि ताकत कैसे काम करती है। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जो कहता है



संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, मूल्य नहीं

संयुक्त राष्ट्र की ओर इशारा करते हुए गुटेरेस ने कहा कि संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने वाले लोग समझते थे कि हमारे संस्थापक दस्तावेजों में निहित मूल्य केवल ऊंचे विचार नहीं थे बल्कि स्थायी शांति और न्याय के लिए अनिवार्य शर्तें थे।

कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुटेरेस ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में, हम ऐसी कार्रवाइयों को चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो ठोस और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करें। हमारे संकटपूर्ण समय में शांति, न्याय, जिम्मेदारी और प्रगति की प्रतिक्रियाएं। महासचिव ने चैन रिएक्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दंड न मिलने का भाव संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, अविश्वাস गहरा रहा है और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत

इस्तांबुल। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डोममेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुपुसी साहिन ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

धोखाधड़ी में 36 भारतीयों सहित दो हजार गिरफ्तार

नोम पेन्ट, एजेंसी

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैंसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानरी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन

● कंबोडिया में कैंसिनो में छापेमारी के दौरान की गई कार्रवाई

नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने कहा कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पिछले सात महीनों में 23 देशों के कुल 5,106 धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इजराइल ने रफाह सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोला

काहिरा। इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की भिंस के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इजराइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है।

ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

न्यूयॉर्क, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा

● अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तेल के लिए चीन भी कर सकता है सौदा

तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी। ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा

आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पुष्टि भी में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्ली रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

आज का भविष्यफल

आज की राह स्थिति : 2 फरवरी, सोमवार 2026 संवत -2082, शक संवत 1947 मारग-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा 3 फरवरी 01.52 तक तत्परचात द्वितीया।

आज का पंचांग

रा.	मं.				
11	गु.	सु.	गु.	9	8
12		10	7		
		4			
2	ब.			6	
	3	गु.	5	के.	

दिशाशुल - पूर्व, ऋतु - शिशिर। **चन्द्रबल** - वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। **ताराबल** - अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती। **नक्षत्र** - अश्लेषा 22.47 तक तत्परचात मघा।

आज आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आएगी। अधिकारी वर्ग आपको अनदेखी कर सकते हैं। विरोधियों को हटके न ले। अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

आज तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी योजनाओं को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें।

आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बात शेयर करने के लिए दिन उसम है। प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा।

आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी प्रतियोगी के साथ सफलता मिल सकती है।

आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यवसाय में आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जीव के अवसर मिलने की संभावना है। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

आज दिन का शुरुआती भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखने को लेकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके ऊपर पुराने ऋण को चुकाने का दबाव हो सकता है। संपत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत होगी।

आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुकेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जीव में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दे। नई जीव दूढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी वित्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरपेशा लोगों को अपनी जीव की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुकेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जीव में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दे। नई जीव दूढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी वित्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरपेशा लोगों को अपनी जीव की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

सुडोकू - 49

सुडोकू - 48 का हल

7	6	5	9	3	1	2	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---



मुझे लगता है कि हमारी टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चेन्नई में हम तीन मैच खेलेंगे और हो सकता है कि वहां की पिच यहां की पिच की तुलना में अलग हो या फिर वैसे ही हो। और अगर ऐसा होता है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है।
-मिचेल सैंटनर

हाईलाइट

लवलीना, पूजा करेंगी भारतीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई

ला नुसिया (स्पेन)। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और ओलंपियन पूजा रानी मंगलवार को स्पेन के एलिकोटे के ला नुसिया में होने वाले बॉक्सिंग एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत की 33 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता हिलेश गुलिया और सचिन सिवाच भी इस टीम का हिस्सा हैं। निकहत जरीन (51 किग्रा) ने मार्च के आखिर में होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते में एक अहम कदम है - की तैयारी पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका

विक आन जी (नीदरलैंड्स)। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को यहां हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसतोरोव ने मैथियास ब्लूबुउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंद के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसतोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया।

अर्शदीप सिंह 'इम्पैक्ट प्लेयर' चुने गए

तिरुवनंतपुरम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के पेसर अर्शदीप सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। बीसीसीआई ने रविवार को ड्रेसिंग रूम का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया। बीसीसीआई टीवी पर शेरार किए गए वीडियो में, ट्रेनिंग असिस्टेंट उडेनका नेवाम ने अर्शदीप सिंह को मेडल जीतने वाले के तौर पर अनाउंस किया, और पूरी सीरीज में लगातार इम्पैक्ट दिखाने के लिए बाएं हाथ के पेसर की तारीफ की। अर्शदीप ने यह सम्मान लेते हुए, स्पॉट स्ट्राफ और फैंस को धन्यवाद दिया और सीरीज के दौरान टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ की।

दो अभ्यास मैच खेलेंगे तिलक वर्मा

मुंबई। भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन (सीआई) से खेलने की मंजूरी मिल गई है और वह 2026 टी20 विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे। जनवरी की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के दौरान लगी चोट के बाद अंडकोष की सर्जरी करने के चलते वे लगभग एक महीने से मैदान से बाहर थे। तिलक पहले 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ इंडिया ए टीम की ओर से खेलेंगे और इसके बाद 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे।

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, एजेंसी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानान्तरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी



बैंकाक, एजेंसी

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने रविवार को यहां 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हिरयाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण

प्रतिद्वंद्वी मलेशिया की गोह जिन वेई बीच से हटीं

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया। बाद में उन्होंने मुकाबला बीच में छोड़ दिया।

मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा मैंने शुरुआत से ही अच्छी गति बनाने की योजना बनाई थी और

वह कारगर रही। मेरा मानना है कि वह थकी हुई थीं और उन्हें ऐंठन भी थी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। देविका इस जीत के साथ सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय

कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास

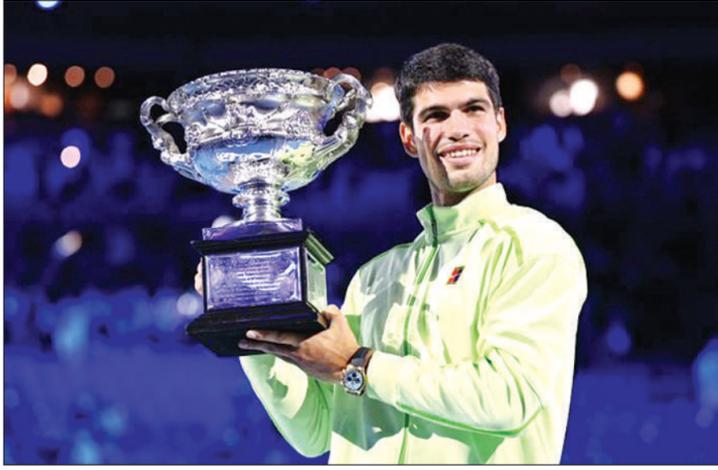
ऑस्ट्रेलियाई ओपन : करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले बने सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी

मेलबर्न, एजेंसी

कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिफॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लेंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, 'काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए।'

बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ



कोई नहीं जानता कि मैं यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने इस पल का बहुत पीछा किया। हमने बस सही काम किया, आम मुझे हर दिन सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं उन सभी का बहुत शुक्रांजलि हूँ जो अभी मेरे साथ हैं।

-कार्लोस अल्कारेज

सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा। पिछले सत्र के आखिर में अल्कारेज

सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दोहफलों के लिए बधाई। आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इंसालिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

-नोवाक जोकोविच

फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके।



उत्तर प्रदेश की कप्तान मेग लानिंग का विकेट लेने के बाद जयम मनाती शिनेल हेनरी।

एजेंसी

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, एजेंसी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानान्तरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी

विदर्भ से हारकर उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी से बाहर

नागपुर। गत चैंपियन विदर्भ ने रविवार को यहां उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन के कारण शीर्ष पर रही।

उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 सलामी में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाड़े 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे। दानिश मालेवार ने भी 54 रन की पारी खेली। उपर की तरफ से स्पिनर शिवम शर्मा ने 55 रन देकर चार विकेट चटकवाए।

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जुड़ा रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिव्यंकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने

दिल्ली ने यूपी को 122 रनों पर रोका

वडोदरा, एजेंसी

महिला प्रीमियर लीग

मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में रविवार को यहां यूपी वारियर्स को आठ विकेट पर 122 रन के स्कोर पर रोक दिया। कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी

वारियर्स ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम कभी बड़े स्कोर की ओर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। वारियर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज दीपति शर्मा (24), शिखा पांडे (नाबाद 23) और सिमरन शेख (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। दिल्ली की टीम अगर इस मुकाबले को



खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग

एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। उन्होंने कहा नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया। सूर्यकुमार ने कहा मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर

देविका ने चैंपियन बनने के बाद कहा आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि यह मेरा पहला सुपर 300 खिताब है। मैं भविष्य में और टूर्नामेंट खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा मैंने यहां बहुत अच्छे मुकाबले खेले। मैंने काफी कुछ सीखा है। यहां मिली सीख को मैं अपने खेल में लागू कर गलतियों को सुधारूंगी। मैच में उतरते समय मैंने जीत या हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान रखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला।

-देविका सिहाग

महिला खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने हासिल की थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स

थाईलैंड मास्टर्स

एक्सप्लोरेशन में कोच उम्रेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा के देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं। भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मेश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। गोह को देविका ने उन्हें कोर्ट पर खूब दौड़ाया।



अंडर-19 में शॉट लगाते वेदांत त्रिवेदी।

एजेंसी

पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

बुलावायो, एजेंसी

अंडर-19 विश्वकप

वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने

● भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन
● पाक को सेमीफाइनल के लिए 33.3 ओवर में हासिल करना था लक्ष्य

समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगवाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गए।

17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, एजेंसी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानान्तरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, एजेंसी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानान्तरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जुड़ा रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिव्यंकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने

एजेंसी